■ RNI No. 58061/93 ■ वर्ष - 21 ■ अंक - 223 ■ पृष्ठ - 8 ■ रु. 5/- बेंगलूरु » शुक्रवार » 13-03-2026 ■ www.dakshinbharat.com ■ Email : news@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूरु और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित

5 किसी को नहीं पता राहुल गांधी किस दुनिया में रहते हैं : सिंह

6 हॉर्मुज की घेराबंदी और भारत में गहराता गैस संकट

7 भावनाओं में बहकर शो छोड़ना आसान है पर जिमेदारी निभाना चुनौती : निक्की तंबोली

फर्स्ट टेक

बैंकों का सर्वर हैक कर करोड़ों रुपए हस्तातंरित करने वाले दो नाइजीरियाई गिरफ्तार

नोएडा (उप्र)/भाषा। नोएडा के सेक्टर-63 में स्थित एक बैंक का सर्वर हैक कर 16 करोड़ 71 लाख रुपये की राशि हस्तांतरित करने के मामले में दो नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। साइबर अपराध थाना पुलिस और नॉलेज पार्क पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इस गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया जबकि अन्य की तलाश जारी है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने पांच मोबाइल फोन, 39 हजार रुपए नगद, चार मोबाइल फोन सिम कार्ड आदि बरामद किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोडेब ओडिक्पो जोसेफ और एस. ओकोनकवों के रूप में हुई है जो नाइजीरिया के नागरिक हैं। उन्होंने बताया कि इनके कुछ साथी फरार हैं।

रुपया 92.25 प्रति डॉलर के सर्वकालिक निचले स्तर पर

मुंबई/भाषा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में बृहस्पतिवार को रुपया 24 पैसे लुढ़ककर 92.25 प्रति डॉलर के अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में जबर्दस्त तेजी तथा विदेशी पूंजी की भारी निकासी के कारण रुपये में यह तेज गिरावट आई। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच घरेलू शेयर बाजारों में भारी बिकवाली और डॉलर के मजबूत होने से भारतीय मुद्रा पर असर पड़ा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 92.25 प्रति डॉलर पर खुला। कारोबार के दौरान इसमें लगातार गिरावट जारी रही और यह डॉलर के मुकाबले अपने रिकॉर्ड निचले स्तर 92.36 को छू गया। कारोबार के अंत में यह 92.25 प्रति डॉलर पर बंद हुआ जो पिछले बंद भाव से 24 पैसे की गिरावट है।

इजराइल ने दक्षिण लेबनान के विशाल क्षेत्र से लोगों को चले जाने की चेतावनी दी

दुबई/एपी। इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान के एक बड़े इलाके के निवासियों को अपने घरों से चले जाने की चेतावनी दी है और कहा है कि वह हिजबुल्ला के खिलाफ 'दृढ़' कार्रवाई करेगी। इजराइली सेना के अरबी भाषा प्रकोष्ठ के प्रवक्ता अविचाई अद्राई ने 'एक्स' पर कहा कि लेबनानी निवासियों को जहरानी नदी के उत्तर में चले जाना चाहिए, जो इजराइल की सीमा से लगभग 56 किलोमीटर दूर है।

प्रधानमंत्री ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा के साथ समझौता किया है : राहुल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

■ राहुल गांधी के मुताबिक नरेन्द्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने में सक्षम नहीं हैं।

नई दिल्ली/भाषा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रसोई गैस (एलपीजी) की किल्लत को लेकर बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा के साथ समझौता किया है। उन्होंने यह भी कहा कि ईंधन की समस्या बढ़ने वाली है और ऐसे में सरकार को समय रहते जरूरी प्रबंध करना चाहिए।

राहुल गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ''मुख्य बात यह है कि रसोई गैस की समस्या होने वाली है, पेट्रोल की समस्या होने वाली है। सभी ईंधन को लेकर समस्या खड़ी होने जा रही है, क्योंकि हमारी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता किया गया है।'' उनक कहना था कि अभी तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी समय है।

राहुल गांधी ने कहा, ''प्रधानमंत्री और सरकार को तुरंत इस समस्या से निकलने के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर तैयारी नहीं की तो करोड़ों लोगों का नुकसान होगा।''

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, ''यह इससे भी बड़ा मुद्दा है कि ईरान हमें ईंधन लेने देता है या नहीं। हम एक अस्थिर दौर में जा रहे हैं। जब आप अस्थिर समय में जाते हैं तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपकी मानसिकता एक जैसी नहीं हो सकती। इसलिए मैं सरकार को जो सुझाव दे रहा हूं वह यह है कि वे संभावनाओं के बारे में गहराई से सोचना शुरू करें और यह सुनिश्चित करने के लिए सोचें कि हमें क्या करना है ताकि लोगों को परेशानी न हो।'' उन्होंने कहा, ''मैं कोई राजनीतिक बयान नहीं दे रहा हूं. मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मुझे आगे बड़ी समस्या नजर आ रही है।'' उनके मुताबिक, यहां एक प्रमुख समस्या है कि प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने में सक्षम नहीं हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने एलपीजी को लेकर दहशत फैलाने वालों पर निशाना साधा

'रसोई गैस के मुद्दे पर कुछ लोग अनावश्यक रूप से दहशत फैला रहे हैं'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

■ पश्चिम एशिया में मौजूदा संकट से देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चत करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में रसोई गैस की स्थिति को लेकर दहशत फैलाने की कोशिश करने वालों पर निशाना साधते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि वे न केवल जनता के सामने खुद को बेनकाब कर रहे हैं बल्कि देश को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं।

यहां 'एनएक्सटी समिट' को संबोधित करते हुए मोदी ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में मौजूदा संकट से कोई भी देश अछूता नहीं है लेकिन भारत इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग मौजूदा हालात का फायदा उठाकर कुछ उत्पादों की कालाबाजारी करने की कोशिश कर रहे हैं और चेतावनी दी कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, मैं राज्य सरकारों से अनुरोध करता हूं कि वे ऐसे समय में कालाबाजारियों और जमाखोरों को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाएं। रसोई गैस के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान में एलपीजी को लेकर काफी चर्चा हो रही है, और कुछ लोग अनावश्यक रूप से दहशत फैला रहे हैं।

मोदी ने कहा, ''मैं इस समय कोई राजनीतिक बयान देना नहीं चाहता। जो लोग दहशत फैला रहे हैं, वे न केवल जनता के सामने अपने इरादों को उजागर कर रहे हैं, बल्कि देश को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं।'' प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार कई मोर्चों पर सक्रिय रूप से काम कर रही है और पिछले कुछ दिनों में उन्होंने पश्चिम एशिया के घटनाक्रम के बारे में कई देशों के नेताओं से बात की है। उन्होंने कहा, हम आपूर्ति शृंखला में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी कि किसानों और नागरिकों को वैश्विक चुनौतियों के बोझ से बचाया जा सके।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष से उत्पन्न मौजूदा संकट से निपटने में हर किसी की महत्वपूर्ण भूमिका है- चाहे वह राजनीतिक दल हों, मीडिया हो, युवा हों, शहर हों या गांव हों। उन्होंने कहा कि हर कोई इस बात से भलीभांति अवगत है कि वैश्विक परिस्थितियां अचानक बदल सकती हैं, जैसा कि लोगों ने हाल के वर्षों में देखा है - चाहे वह कोविड-19 महामारी की शुरुआत हो, रूस-यूक्रेन संकट हो, या अब घर के करीब एक बड़े संघर्ष का बढ़ना हो।

तूतीकोरिन में बारहवीं कक्षा की एक छात्रा की हत्या

तमिलनाडु के विपक्षी दल ने यौन हमले का लगाया आरोप

तूतीकोरिन (तमिलनाडु)/भाषा। तूतीकोरिन में 12 वीं कक्षा की 17 वर्षीय एक छात्रा की हत्या के बाद तमिलनाडु में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। यह लड़की 10 मार्च को लापता हो गयी थी और 11 मार्च को वेदनाथम में उसके घर के पास उसका शव मिला। उसकी हत्या कर दी गयी थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, लड़की के माता-पिता ने 10 मार्च की रात को कुलथुर थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी, क्योंकि वह घर नहीं लौटी थी। अगले दिन तलाश के दौरान ग्रामीणों को उसके घर के पास झाड़ियों में उसका शव नजर आया। पुलिस ने बताया कि लड़की का गला घोंट जाने के निशान था और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उसने कहा कि आगे की कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बृहस्पतिवार विपक्ष के नेता और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के महासचिव के पलानीसामी ने आरोप लगाया कि लड़की के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। उन्होंने यह भी दावा किया कि जब माता-पिता ने लड़की के लापता होने की सूचना दी, तो पुलिस ने ढिलाई बरती। पलानीसामी ने कहा, ''इस शर्मनाक कृत्य ने द्रमुक सरकार के चरित्र को उजागर कर दिया है।'' उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर रहे पीड़ित परिवार के साथ बातचीत में सत्ताधारी पार्टी के विधायक की संलिप्तता पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, द्रमुक विधायक को शांति वार्ता करने क्यों आना चाहिए? क्या द्रमुक या द्रमुक सरकार कुछ छिपाने, मामले को कमजोर करने या किसी तरह से अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है?

ईंधन संकट की आशंका से

देशभर में अफरा-तफरी, पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। ईंधन की कथित कमी की खबरों के बीच बृहस्पतिवार को देशभर में लोग पेट्रोल पंपों और एलपीजी वितरण केंद्रों के बाहर लंबी कतारों में खड़े नजर आए, जिससे आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ रेस्तरां, स्कूलों और खानपान सेवाओं का कामकाज भी प्रभावित होने लगा है। हालांकि सरकार ने संसद में कहा कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की कोई कमी नहीं है और यह अफवाहें फैलाने का समय नहीं है।

उत्तराखंड सरकार ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर वाणिज्यिक गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्णय किया है और जरूरत पड़ने पर व्यावसायिक उपयोग के लिए लकड़ी उपलब्ध कराने की तैयारी भी शुरू कर दी है।

काफी हद तक वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर पर निर्भर भोजनालयों और त्वरित सेवा रेस्तरां शृंखला में डर है कि आपूर्ति में पाबंदियां लगने से उनका कामकाज बाधित हो सकता है और लागत बढ़ सकती है।

देश के कई हिस्सों में कुछ भोजनालयों को अपना कामकाज सीमित करना पड़ा है।

'तमिलनाडु होटल्स एसोसिएशन' के अनुसार राज्य में छोटे और मध्यम रेस्तरां बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। चेन्नई के कई प्रतिष्ठित भोजनालयों को घटते गैस भंडार को बचाने के लिए डोसा और 'फ्राइड राइस' जैसे ज्यादा गैस खपत वाले व्यंजन परोसना बंद करना पड़ा है।

दिल्ली के एक रेस्तरां मालिक ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, सिलेंडर की कमी है। दोगुनी कीमत करीब 1,500 से 2,000 रुपये देने पर भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके रेस्तरां को रोज कम से कम तीन सिलेंडरों की जरूरत पड़ती है। पश्चिम बंगाल में, अधिकारियों ने कहा रसोई गैस सिलेंडर की कथित कमी का असर राज्य के कई स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना पर भी पड़ने लगा है।

इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल पर परीक्षण किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु/भाषा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने तमिलनाडु के महेंद्रगिरि स्थित अपने प्रणोदन परिसर में नोजल सुरक्षा प्रणाली और बहु-तत्व इग्नाइटर का इस्तेमाल करते हुए 22 टन थ्रस्ट स्तर पर अपने क्रायोजेनिक इंजन (सीई20) का समुद्र तल पर सफलतापूर्वक परीक्षण (हॉट टेस्ट) किया है।

इससे पहले, नोजल सुरक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए समुद्र तल परीक्षण 19 टन थ्रस्ट स्तर पर किए जा रहे थे। सीई20 क्रायोजेनिक इंजन 'लॉन्च व्हीकल मार्क-3' (एलवीएम3) के ऊपरी क्रायोजेनिक चरण को शक्ति प्रदान करता है।

इसरो ने अपनी वेबसाइट पर एक पोस्ट में कहा, ''एलवीएम3 वाहन की भार वहन क्षमता को बढ़ाने के लिए, एलवीएम3 के भावी मिशनों को उन्नत सी32 चरण के साथ संचालित करने की योजना है, जिसमें सीई20 इंजन के लिए 22 टन का थ्रस्ट होगा।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, सीई20 इंजन का उड़ान स्वीकृति परीक्षण भी 22 टन थ्रस्ट स्तर पर आयोजित किया जाना आवश्यक है।''

ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है : राष्ट्रपति ट्रंप

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

वाशिंगटन/भाषा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बृहस्पतिवार को कहा कि ईरान में ''दमनकारी साम्राज्य'' को रोकना उनके लिए तेल की कीमतों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

अमेरिका और इजराइल द्वारा 28 फरवरी को ईरान पर हमला शुरू करने के बाद से तेल की कीमतें उच्च स्तर पर बनी हुई हैं। पश्चिम एशिया में जहाजों और तेल अवसंरचना पर ईरानी हमलों के कारण कच्चे तेल की कीमतें 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं।

ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में कहा, ''अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, इसलिए जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो हमें बहुत फायदा होता है। लेकिन राष्ट्रपति के रूप में मेरे लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है, ताकि वह पश्चिम एशिया और वास्तव में पूरी दुनिया को नष्ट न कर दे।''

ईरान पर हमले शुरू होने के बाद से विदेश मंत्री मार्को रुबियो समेत व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने सांसदों के साथ वार्ता की हैं। हालांकि, ऐसी खबरें भी हैं कि ट्रंप युद्ध में हासिल की गई प्रगति को लेकर मिले-जुले संकेत दे रहे हैं।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में मीडिया पर 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' के उद्देश्यों के बारे में मिली-जुली जानकारी फैलाने का आरोप लगाया।

ईरान के शीर्ष नेता ने हमलों को जारी रखने का संकल्प जताया

दुबई/एपी। अपने दिवंगत पिता की जगह संभालने के बाद ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने पहला बयान जारी कर बृहस्पतिवार को कहा कि ईरान अपने खाड़ी अरब के पड़ोसियों पर हमले जारी रखेगा और होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने के रणनीतिक लाभ का इस्तेमाल अमेरिका व इजराइल के खिलाफ दबाव के लिये करेगा।

सरकारी टेलीविजन पर शीर्ष नेता खामेनेई (56) का बयान एक समाचार प्रस्तोता द्वारा पढ़ा गया। खामेनेई कैमरे के सामने नहीं आए और इजराइली आकलन से पता चलता है कि युद्ध की शुरुआती गोलीबारी में वह घायल हो गए थे। उन्होंने एक स्कूल पर हुए हमले में मारे गए 165 लोगों समेत युद्ध में मारे गए लोगों का बदला लेने का संकल्प जताया।

इस बयान से उस युद्ध को जारी रखने की इच्छा का संकेत मिलता है जिसने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय यात्रा और खाड़ी अरब देशों को प्राप्त सापेक्ष सुरक्षा को बाधित किया है, और जिसने ईरान के नेतृत्व, सैन्य और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर भी भारी असर डाला है। युद्ध शुरू होने के बाद से खामेनेई को सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। फारस की खाड़ी में पोत परिवहन और ऊर्जा अवसंरचना पर ईरान के लगातार हमलों के कारण बृहस्पतिवार को तेल की कीमतें फिर से 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं।

भारत होर्मुज से अपने व्यापारिक जहाजों के सुरक्षित मार्ग के लिए ईरान के संपर्क में

नई दिल्ली/भाषा। भारत होर्मुज जलडमरूमध्य के रणनीतिक जहाजरानी मार्ग से भारतीय ध्वज वाले लगभग 28 व्यापारिक जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने को लेकर ईरान के साथ संपर्क में है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। अमेरिका और इजराइल के साथ संघर्ष के बीच ईरान ने इस मार्ग को आंशिक रूप से अवरुद्ध कर दिया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके ईरानी समकक्ष के बीच हुई बातचीत के दौरान जहाजरानी की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित मुद्दे उठे थे। पता चला है कि ईरान ने पिछले चार-पांच दिन में भारतीय ध्वज वाले किसी भी वाणिज्यिक टैंकर को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति नहीं दी है। पोत परिवहन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, वर्तमान में होर्मुज जलडमरूमध्य के पश्चिम में भारतीय ध्वज वाले कुल 24 जहाज 677 भारतीय नाविकों के साथ मौजूद हैं, जबकि रणनीतिक जलमार्ग के पूर्व में 101 भारतीय नाविकों वाले चार

भारत ने हालिया पाक-तालिबान सीमा संघर्ष पर पाकिस्तान के 'बयान' को खारिज किया

नई दिल्ली/भाषा। भारत ने बृहस्पतिवार को पाकिस्तानी सैनिकों और तालिबान के बीच हालिया झड़पों में भारतीय हाथ होने के पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी तरह की कहानी इस तथ्य को नहीं बदल सकती कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करता है। भारत ने भारत-कनाडा यूरेनियम समझौते पर पाकिस्तान की आलोचना को भी खारिज कर दिया और उसकी प्रतिक्रिया को हास्यास्पद और उसके बेहद खराब प्रदर्शन से ध्यान भटकाने का प्रयास बताया। पाकिस्तान-तालिबान सीमा विवाद से संबंधित पाक के आरोपों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अपनी गलतियों के लिए भारत को दोषी ठहराना पाकिस्तान की आदत बन गई है। जायसवाल ने अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, मैं यह कहना चाहूंगा कि हम ऐसे निराधार आरोपों को खारिज करते हैं। अपनी गलतियों के लिए भारत को दोषी ठहराना पाकिस्तान की आदत सी बन गई है।

'ताजमहल का नाम बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं'

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि ताजमहल का नाम बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान माकपा के जॉन ब्रिटास ने पूरक प्रश्न पूछा कि क्या ताजमहल का नाम बदलने की सरकार की कोई योजना है। इस पर शेखावत ने कहा ''नाम बदलने का मंत्रालय का कोई विचार नहीं है। उन्होंने सदन को बताया कि मोदी सरकार ने 10 वर्षों में ऐतिहासिक स्थलों के उत्खनन पर पिछली सरकारों के 10 वर्षों की तुलना में दोगुनी राशि खर्च की है। तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय ने जानना चाहा कि क्या पश्चिम बंगाल में और ऐतिहासिक स्थलों का उत्खनन करने की योजना है। इस पर शेखावत ने कहा कि उत्खनन एक सतत प्रक्रिया है और यह उपलब्ध मानव संसाधनों पर निर्भर करता है।

सूर्यास्त	सूर्योदय
12-03-2026 6:30 बजे	13-03-2026 6:28 बजे

BSE	NSE
76,034.42 (-829.29)	23,639.15 (-227.70)

सोना	चांदी
16,703 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम	274,808 रु. प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

हाजिर हो

जनप्रतिनिधि का दायित्व यही,
कर्तव्यों पर वे रहे स्थित।
बहुमूल्य वोट देकर उनको,
हमने चाहा जन-जन का हित।
संसद है पूजा स्थल उनका,
जब खुले रहे तब हाजिर नित।
वर्ना पूछेगी जनता अब,
क्यों रहे सदन से अनुपस्थित।।

होर्मुज से होकर एक तेल टैंकर मुंबई पहुंचा, एक अन्य पारादीप की राह पर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत के लिए कच्चा तेल लेकर आ रहा एक विदेशी ध्वज वाला टैंकर होर्मुज जलडमरूमध्य को सकुशल पार कर मुंबई पहुंच गया है जबकि एक अन्य बड़ा टैंकर भारतीय जलक्षेत्र में प्रवेश कर ओडिशा के पारादीप बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा है। यह जानकारी जहाज निगरानी आंकड़ों और उद्योग सूत्रों से मिली है।

क्षेत्र में बढ़ते संघर्ष के कारण जलडमरूमध्य से टैंकर की आवाजाही काफी हद तक प्रभावित हुई है। ऐसे में इन जहाजों का सुरक्षित पहुंचना भारत की ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है।

लाइबेरिया के ध्वज वाला टैंकर 'शेनलांग' सऊदी अरब से लगभग 10 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर बुधवार शाम मुंबई बंदरगाह पहुंच गया। यह जहाज तीन मार्च को सऊदी अरब के रास तानुरा बंदरगाह से तेल लादकर रवाना हुआ था।

जहाज ने होर्मुज जलडमरूमध्य के पास अपना अंतिम सिग्नल नौ मार्च को प्रसारित किया था। उसके बाद जहाज की स्वचालित पहचान प्रणाली (एआईएस) कुछ समय के लिए बंद कर दी गई थी। संभवतः इसी दौरान जहाज ने इस जलडमरूमध्य को पार किया। बाद में वह फिर जहाज निगरानी

प्रणाली पर नजर आने लगा।

उद्योग सूत्रों ने कहा कि बुधवार को मुंबई बंदरगाह पर इस टैंकर के पहुंच जाने के बाद अब जहाज से तेल उतारने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

इसके अलावा, एक अन्य तेल टैंकर भी करीब 20 लाख बैरल इराकी कच्चा तेल लेकर भारतीय समुद्री क्षेत्र में पहुंच चुका है। भारतीय ध्वज वाला यह बहुत बड़ा टैंकर पारादीप की तरफ जा रहा है, जहां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी स्थित है।

भारत अपनी कुल तेल जरूरतों का लगभग 88 प्रतिशत आयात करता है और इसका बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते ही आता है।

ऐसी स्थिति में जलडमरूमध्य के मार्ग से तेल एवं गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने ईरान के अधिकारियों से संपर्क साधा हुआ है। इस बीच, ऐसी अपुष्ट खबरें भी आई हैं जिनके मुताबिक ईरान ने भारतीय ध्वज वाले जहाजों को जलडमरूमध्य से सुरक्षित रास्ता देने पर सहमति जता दी है।

हालांकि, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इन खबरों को सही या गलत ठहराने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, ''विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के बीच हाल में तीन बार बातचीत हुई है। आखिरी बातचीत में दोनों पक्षों ने समुद्री जहाजों की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। अभी इस पर अधिक विवरण साझा करना जल्दबाजी होगी।''

पोत परिवहन मंत्रालय में संयुक्त सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से 28 भारतीय जहाज फंस गए हैं। इन जहाजों पर सवार नाविकों की सुरक्षा के लिए लगातार नजर रखी जा रही है।

दूध उत्पादकों, विक्रेताओं के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना जरूरी : खाद्य नियामक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। देश के कुछ हिस्सों में मिलावट की खबरों के बीच खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को छोड़कर, सभी दूध उत्पादकों और दूध विक्रेताओं के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र लेना ज़रूरी कर दिया है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य खाद्य आयुक्तों को दूध उत्पादक (डेयरी सहकारी समिति के सदस्यों को छोड़कर) और दूध विक्रेताओं के लिए ज़रूरी पंजीकरण/लाइसेंस के बारे में एक परामर्श जारी किया है।

नियामक ने बताया कि कुछ दूध उत्पादक और दूध विक्रेता खाद्य व्यवसाय गतिविधियां करने के लिए खुद को पंजीकृत किए बिना या लाइसेंस लिए बिना काम कर रहे हैं।

नियामक ने कहा, ''सभी दूध उत्पादकों (उनके अलावा जो सहकारी समिति कानून के तहत डेयरी सहकारी समिति के पंजीकृत सदस्य हैं) और दूध बेचने वालों को सलाह दी जाती है कि वे अपना काम शुरू करने या जारी रखने से पहले एफएसएसएआई के साथ खुद को ज़रूरी तौर पर पंजीकृत करें।''

एफएसएसएआई ने राज्य के खाद्य आयुक्तों से कहा, ''सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में दूध में मिलावट की हालिया घटनाओं को देखते हुए, पंजीकरण-लाइसेंसिंग की ज़रूरतों का सख्ती से पालन किया जाएगा।''

दिल्ली पुलिस ने जलती हुई मटियाला झुग्गी बस्ती में विस्फोट होने से रोका

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के मटियाला इलाके में एक बड़ा विस्फोट उस वक्त टल गया, जब दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने सीएनजी से चलने वाली एक बंद कार की खिड़की तोड़कर उसे भीषण आग से दूर हटा दिया। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

मानसराम पार्क इलाके में बुधवार देर रात एक झुग्गी बस्ती में आग लग गई। भीषण आग के कारण 400 से अधिक झुग्गियां नष्ट हो गईं। पुलिस उपायुक्त (पीसीआर) पवन कुमार के अनुसार, बिंदापुर पुलिस थाने को रात 11.57 बजे आग लगने की सूचना मिली। स्थानीय पुलिस दल और पीसीआर इकाइयां निवासियों को सुरक्षित निकालने में सहायता के लिए मौके पर पहुंचीं। हेड कांस्टेबल रामरतन सरन ने फैलती हुई आग के बिल्कुल पास खड़ी एक बंद कार को देखा। वाहन में सीएनजी किट लगी होने और अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट का खतरा होने का एहसास होने पर, अधिकारी ने पत्थर से कार का शीशा तोड़ दिया और उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले गए। सरन ने बताया, ''आग गाड़ी के बहुत करीब तक पहुंच गई थी। यह एक नई सीएनजी कार थी और गैस भरी थी। चूंकि गाड़ी लॉक थी, इसलिए मैंने खिड़की तोड़कर उसे दूर हटाया।'' पुलिस उपायुक्त (द्वारका) कुशलपाल सिंह ने कहा कि अधिकारी के समय पर हस्तक्षेप से एक बड़ी घटना टल गई। बाद में दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक फेसबुक हैंडल पर घटना के दृश्य साझा किए और हेड कांस्टेबल की विवेकपूर्ण कार्रवाई की प्रशंसा की। पुलिस ने पोस्ट में लिखा, बिंदापुर की झुग्गी बस्ती में लगी आग के दौरान, घटनास्थल पर मौजूद पीसीआर यूनिट में तैनात हेड कांस्टेबल रामरतन सरन ने आग के करीब खड़ी एक कार को देखा और विस्फोट की आशंका को भांपते हुए कार का शीशा तोड़ दिया और वाहन को समय रहते हटा दिया। इस सूझबूझपूर्ण कार्रवाई से एक बड़ी दुर्घटना टल गई।

बम की धमकी वाले ईमेल को पश्चिम एशिया संघर्ष से न जोड़ें : योगेश कदम

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री (शहर) योगेश कदम ने बृहस्पतिवार को कहा कि विधान भवन और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) सहित प्रमुख इमारतों पर ''मिसाइल और बम हमलों'' की धमकी भरे ईमेल को पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। कांग्रेस ने मामले की गहन जांच की मांग की।

विधान परिषद के सभापति राम शिंदे ने कहा कि विधान परिषद के आधिकारिक ईमेल खाते पर सुबह छह बजकर 57 मिनट पर प्राप्त इस ईमेल में विधान भवन परिसर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई मेट्रो और एक बैंक पर संभावित हमलों का जिक्र किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर विधान भवन परिसर में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। दक्षिण मुंबई स्थित विधान भवन में इस समय बजट सत्र जारी है और परिसर को सुरक्षित बताया गया है। पत्रकारों से बातचीत में कदम ने कहा कि अधिकारी ईमेल के स्रोत और प्रेषक की पहचान का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इस तरह के फर्जी ईमेल कभी-कभी आते रहते हैं, लेकिन विधान भवन सुरक्षित है। पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी है, लेकिन इस ईमेल को उस संघर्ष से जोड़ना सही नहीं होगा। मुंबई और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा की समीक्षा की गई है।

गोवा में घरेलू रसोई गैस की कमी नहीं : सावंत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पणजी/भाषा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बृहस्पतिवार को कहा कि घरेलू उपयोग के लिए रसोई गैस (एलपीजी) की कोई कमी नहीं है, हालांकि राज्य के विभिन्न हिस्सों में गैस वितरकों के बाहर लंबी कतारें देखी गईं। सावंत ने कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हुई है।

बृहस्पतिवार को विधानसभा की बैठक शुरू होने पर विपक्ष ने राज्य में एलपीजी की कथित कमी का मुद्दा उठाया।

विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ ने दावा किया कि गोवा में एलपीजी सिलेंडर वितरकों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में उत्पन्न ''आपातकालीन'' स्थिति के बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए।

इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि घरेलू रसोई गैस की कोई कमी नहीं है, हालांकि व्यावसायिक इकाइयों के लिए एलपीजी की आपूर्ति में समस्या है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर केंद्र के संपर्क में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपूर्ति के बारे में केंद्र से विवरण मांगेगी और स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने नेटफ्लिक्स के 'आईलाइन स्टूडियोज' का उद्घाटन किया

हैदराबाद/भाषा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने बृहस्पतिवार को यहां नेटफ्लिक्स 'आईलाइन स्टूडियोज' के ग्लोबल वीएफएक्स और वर्चुअल प्रोडक्शन केंद्र का उद्घाटन किया तथा ओटीटी क्षेत्र की अग्रणी कंपनी को राज्य सरकार द्वारा शहर के बाहरी इलाके में विकसित किए जा रहे 'भारत फ्यूचर सिटी' में एक बड़ा केंद्र स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। आईलाइन नेटफ्लिक्स का इनोवेशन हब है। रेड्डी ने सभी फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 'भारत फ्यूचर सिटी' लाने का वादा किया।

हैदराबाद को अंतरराष्ट्रीय फिल्म उद्योग का केंद्र बनाने के अपने सपने का जिक्र करते हुए रेड्डी ने कहा कि शहर में नेटफ्लिक्स द्वारा केंद्र स्थापित करने का मतलब हॉलीवुड का आगमन है। उन्होंने कहा, यह मेरे सपने की पहली सीढ़ी है। यह जगह सिर्फ टॉलीवुड, बॉलीवुड, कॉलीवुड के लिए ही नहीं है। मैं हॉलीवुड पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। आज मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि नेटफ्लिक्स यहां आ गया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हॉलीवुड यहां पहुंच गया है। मेरा सपना सच होने जा रहा है। मैं नेटफ्लिक्स का स्वागत करता हूं। उन्होंने नेटफ्लिक्स से हैदराबाद में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह करते हुए ओटीटी मंच को सरकार के समर्थन का आश्वासन दिया। उद्घाटन समारोह में राज्य के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्रीधर बाबू, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू और अभिनेता-निर्माता राणा दग्गुबाती के साथ-साथ आईलाइन स्टूडियोज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेफ शापिरो भी उपस्थित थे। आईलाइन स्टूडियोज नेटफ्लिक्स का दृश्य प्रभाव (विजुअल इफेक्ट्स) और वर्चुअल प्रोडक्शन के लिए प्रमुख नवाचार केंद्र है, जहां व्यावहारिक फिल्म निर्माण और अगली पीढ़ी की तकनीक का संगम होता है।

फारूक अब्दुल्ला की हत्या के प्रयास पर शरद पवार ने कहा: गहरी चिंता का विषय

मुंबई/भाषा। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हुए हत्या के प्रयास को बृहस्पतिवार को गहरी चिंता का विषय करार दिया।

पवार ने 'एक्स' पर पर लिखा, ''वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला और उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी की मौजूदगी में एक शादी समारोह में हुई गोलीबारी की घटना गहरे चिंता का विषय है। सौभाग्य से, किसी को कोई चोट नहीं आई, जो बड़ी राहत की बात है। उन्होंने आगे कहा, हालांकि, ऐसी घटनाएं सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं। यह जानकर राहत मिलती है कि सभी गणमान्य व्यक्ति सुरक्षित हैं। उनकी स्वास्थ्य, लंबी उम्र और निरंतर सुरक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनायें।'' नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ राजनेता अब्दुल्ला (88) को बुधवार रात जम्मू के बाहरी इलाके, ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में एक विवाह समारोह हॉल से निकलते समय नज़दीकी दूरी से निशाना बनाने की कोशिश की गई।

सरकार दो संकट पैदा कर रही, 'सरेंडर क्राइसिस' और 'सिलेंडर क्राइसिस' : कांग्रेस सांसद

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस सांसद शफी परम्बिल ने देश में ''एलपीजी संकट'' को लेकर बृहस्पतिवार को सरकार पर आरोप लगाया कि वह दो तरह के संकट पैदा कर रही है, 'सरेंडर क्राइसिस' और 'सिलेंडर क्राइसिस'। उन्होंने मीडिया में आई खबरों का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय में वकीलों की कैंटीन में एलपीजी गैस की कमी के कारण अस्थायी रूप से 'मेन कोर्स' का खाना देना बंद कर दिया गया है।

वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांग के दूसरे बैच पर लोकसभा में चर्चा में हिस्सा लेते हुए, उन्होंने कहा कि ''एलपीजी संकट'' के कारण बेंगलूरु में होटल से लेकर घरों तक, सभी परिवार दहशत में आ गए हैं, नोएडा में रसोई गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतार लग रही है और विभिन्न शहरों में हर परिवार संकट में है। उन्होंने कहा कि रसोई गैस की आपूर्ति में कमी और युद्ध के कारण उत्पन्न हुए संकट से निपटने के सरकार के तरीके ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है।

कांग्रेस सांसद ने कहा, ''मैं कहना चाहूंगा कि सरकार दो संकट पैदा कर रही है -- पहला, सरेंडर क्राइसिस और दूसरा, सिलेंडर क्राइसिस।'' उन्होंने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने के संबंध में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई टिप्पणी को उद्धृत किया, जिस पर सत्तापक्ष के सदस्यों की ओर से कड़ी आपत्ति जताई गई।

भाजपा के निशिकांत दुबे ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, ''नियम 216 यह कहता है कि जब अनुदान की मांग पर आप चर्चा करते हैं तो अन्य विषय पर चर्चा नहीं कर सकते। जिन मांगों को सरकार लेकर आकर आई है, केवल उसी पर अपनी बात रखिये। किसी नीतिगत विषय पर या किसी अन्य विषय पर आप बोल नहीं सकते।''

अजित पवार विमान हादसे की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की आवश्यकता : राहुल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान से जुड़े हादसे की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कानून के बुनियादी सिद्धांतों का पालन नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शप) के विधायक रोहित पवार ने राहुल गांधी से मुलाकात कर उन्हें मामले के तथ्यों से अवगत कराया। राहुल गांधी ने पोस्ट किया, ''रोहित पवार ने आज मुझसे मुलाकात की और बारामती विमान दुर्घटना की जांच के बारे में गंभीर चिंता जताते हुए पत्र सौंपा, जिसमें अजित पवार जी और अन्य लोगों की जान चली गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कानून के बुनियादी सिद्धांतों का पालन नहीं किया और मामले की गंभीरता के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।''

पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद से निवेशकों की संपत्ति 23.44 लाख करोड़ रुपए घटी

नई दिल्ली/भाषा। पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से अबतक निवेशकों की संपत्ति 23.44 लाख करोड़ रुपए घट गई है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले से शेयर बाजारों में तेज गिरावट आई है और बीएसई सेंसेक्स छह प्रतिशत से अधिक नीचे आया है।

इस संघर्ष के कारण फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित संकरे जलमार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इससे वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 6.66 प्रतिशत बढ़कर 98.11 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गया। शेयर बाजार में 27 फरवरी से, 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 5,252.77 अंक यानी 6.46 प्रतिशत नीचे आया है। इस दौरान बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 23,44,237.26 करोड़ रुपए घटकर 4,40,06,434.01 करोड़ रुपए (4,770 अरब डॉलर) हो गया। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स बृहस्पतिवार को 829.29 अंक यानी 1.08 प्रतिशत टूटकर 76,034.42 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 992.53 अंक लुढ़क कर 75,871.18 अंक पर आ गया था।

जम्मू में पाक ड्रोन से गिराई गई 12 करोड़ रुपए कीमत की हेरोइन बरामद

जम्मू/भाषा। जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा गिराई गई करीब दो किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए आंकी गई है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, जम्मू पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की 101वीं बटालियन ने बुधवार देर रात बिश्राह क्षेत्र के बहादुरपुरा गांव में एक खेत से यह हेरोइन बरामद की।

पुलिस ने बताया कि संदिग्ध ड्रोन से सामान गिराए जाने की सूचना पर कार्रवाई करते हुए तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस दौरान रस्सी और हुक से जुड़ा एक बैग बरामद हुआ जिसमें हेरोइन के छोटे पैकेट थे। पुलिस ने इस बरामदगी को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि करार दिया है।

अय्यर और थरूर के बीच आरोप-प्रत्यारोप, दोनों ने लिखे 'खुले पत्र'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने एक खुला पत्र लिखकर पार्टी सांसद शशि थरूर पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब उनसे किसी तरह का संबंध नहीं है, जिसको लेकर थरूर ने पलटवार किया कि अय्यर ने बहुत सारी अनावश्यक टिप्पणियां की हैं।

दोनों के बीच आरोप-प्रत्यारोप की शुरुआत उस वक्त हुई जब अय्यर द्वारा थरूर को एक खुला पत्र लिखा गया जो इस सप्ताह की शुरुआत में 'फ्रंटलाइन' पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अय्यर ने कहा कि वह छह मार्च को एक टीवी चैनल पर इजराइल द्वारा अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ छेड़े गए ''अवैध युद्ध'' पर थरूर के सवालों के जवाब से काफी हैरान थे। अय्यर ने लिखा, ''मैं इतना परेशान हो गया हूं कि सो नहीं सका और सुबह तीन बजे उठकर आपको यह खुला पत्र लिख रहा हूं।'' अय्यर ने दावा किया कि उन्होंने न केवल कांग्रेस अध्यक्ष पद

के चुनाव में थरूर को वोट देकर अपना राजनीतिक करियर दांव पर लगाया, जबकि उन्हें पता था कि थरूर बुरी तरह हारेंगे, बल्कि अगले दिन 'द इंडियन एक्सप्रेस' में यह (आलेख) लिखकर भी कहा कि विजेता मल्लिकार्जुन खरगे को गांधी परिवार और 'जी-23' समूह के कुछ लोगों के समर्थन के बावजूद उनके खिलाफ खड़े होने के (थरूर के) लोकतांत्रिक अधिकार का उदारतापूर्वक सम्मान करना चाहिए। उन्होंने लेख में कहा, ''लेकिन कुछ शुरुआती संकेत थे कि आप 'हम में से एक' नहीं थे। अब, एक ऐसे शासन के प्रति आपकी गहरी सहानुभूति ने इस पर पड़े पर्दे को हटा दिया है...यह रास्ते अलग होने का मामला है।

अय्यर पर पलटवार करते हुए, थरूर ने एक खुला पत्र लिखा, जिसे एनडीटीवी ने बृहस्पतिवार को प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि असहमति एक समृद्ध लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन किसी सहयोगी के इरादों या देशभक्ति पर सिर्फ इसलिए सवाल उठाना उचित नहीं है कि वह विदेश नीति के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। थरूर ने कहा, हालांकि आप अपने विचार रखने के हकदार हैं, मेरा रुख (और मेरे चरित्र) का आपका हालिया सार्वजनिक 'मूल्यांकन' स्पष्ट प्रतिक्रिया की मांग करता है।'' थरूर ने कहा, मैंने हमेशा अंतरराष्ट्रीय मामलों को स्पष्ट राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से देखा है, भारत के हितों, सुरक्षा और वैश्विक स्थिति को हर चर्चा के केंद्र में रखा है।

गांवों से अपनापन नदारद, अब तो केवल नफरत और समस्याएं ही नजर आती हैं : कांग्रेस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राज्यसभा में बृहस्पतिवार को कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार पर गांवों में अपनापन और प्यार समाप्त करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब गांवों में केवल नफरत और समस्याएं ही नजर आती हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर उच्च सदन में चर्चा में हिस्सा ले रहे प्रतापगढ़ी ने कहा कि पहले गांवों में अपनापन और प्यार होता था लेकिन 2014 के बाद से केवल नफरत और समस्याएं ही नजर आती हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हो रही है लेकिन गांवों से जुड़ा हर वर्ग परेशान है। उन्होंने कहा कि गांवों के लोगों को रोजगार मुहैया कराने वाली योजना ''मनरेगा'' को आगे बढ़ाने के बजाय उसे सरकार खत्म करना चाहती है। ''नाम बदलना तो केवल एक बहाना है।'' प्रतापगढ़ी ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सफलता का दावा कर अपनी पीठ थपथपाती है लेकिन किसी भी राज्य में देखिये, सड़कों की हालत खराब है। ''बीमार व्यक्ति तो उन सड़कों से अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाता और गर्भवती महिलाओं को इन सड़कों से अस्पताल पहुंचाना दूभर हो जाता है।'' उन्होंने कहा कि किसान लगातार अपनी मांगों को ले कर खड़े रहे लेकिन इस सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। उनके अनुसार, किसानों की हालत आज भी नहीं सुधरी और उनकी आमदनी नहीं बढ़ी। ''किसान अपनी मेहनत से अन्न उपजाता है लेकिन सरकार उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं देती।'' कांग्रेस सदस्य ने कहा ''हम तो गांवों से शहर पलायन नहीं करने का सपना देखते थे लेकिन गांवों को जिस तरह मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है उससे साफ है कि गांव के लोगों के लिए पलायन करना मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी के बाबूराम निषाद ने कहा कि आलोचना करना अलग बात है लेकिन अगर गांवों का विकास नहीं हुआ होता तो उथल-पुथल के इस दौर में भारत इतनी मजबूती से नहीं खड़ा होता। यह विकास 2014 के बाद से हुआ है और गांवों की तस्वीर बदली है।

बेलगाम में आईटी-बीटी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगी सरकार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि सरकार बेलगाम को राज्य का एक प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र बनाने और उत्तरी कर्नाटक के युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लागू कर रही है। गुरुवार को विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान, मंत्री ने परिषद के सदस्य एम. नागराजू के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि बेलगाम में तत्काल मांग को पूरा करने के लिए जिला कलेक्टर को कला मंदिर जैसे स्थानों पर आईटी प्लग-एंड-प्ले केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, केएलई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और मराठा मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज में तीन प्रौद्योगिकी व्यापार इनक्यूबेटर स्थापित किए गए हैं। छात्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए केएलई फार्मेसी कॉलेज और एसजी बालेकुंद्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 'न्यू एज इनोवेशन नेटवर्क' केंद्र शुरू किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि पहली बार, अगस्त में बेलगावी के सुवर्ण विधान सौधा में एक विशाल प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 'टेकसेलरेशन-2025' का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में 700 से अधिक प्रतिनिधियों और विदेशी प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। हुब्बल्ली-धारवाड़-बेलगावी क्लस्टर से रिकॉर्ड 52 स्टार्टअप आवेदनों में से, शीर्ष 10 को बैंगलोर टेक समिट-2025 में मुफ्त बूथ प्रदान करके समर्थन दिया गया।

सरकार निपुण कर्नाटक योजना के तहत युवाओं और उद्यमियों के लिए आवश्यक कौशल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर रही है ताकि उन्हें आईटी उद्योग के लिए आवश्यक कौशल प्रदान किए जा सकें। आइडिया 2 पीओसी-एलिवेट के तहत नवोन्मेषी स्टार्टअप्स को 50 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है।

राजीव गांधी उद्यमिता कार्यक्रम के तहत, 30 महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को विशेष सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें युवा स्नातकों को नए विचारों को लागू करने के लिए 12 महीने की अवधि के लिए 25,000 रुपये का मासिक वजीफा शामिल है। मंत्री ने सदन को सूचित किया कि सरकार बियॉन्ड बेंगलूरु कार्यक्रम के तहत बेलगाम को एयरोस्पेस, सीआरपीओ-टेक और इंडस्ट्री 4.0 क्षेत्रों के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सभी सरकारी अस्पतालों के लिए जीवन रक्षक आवश्यक दवाएं खरीदने के लिए कदम उठाए गए हैं : गुंडूराव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में जीवन रक्षक आवश्यक दवाओं की शीघ्र खरीद और वितरण करने तथा मरीजों को उन्हें मुफ्त में वितरित करने के लिए एएसओएसआई द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। गुरुवार को विधानसभा के प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान कुश्तगी विधानसभा क्षेत्र के सांसद डोड्डानागौड़ा हनुमगौड़ा पाटिल द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों को विभिन्न सरकारी अनुदानों का उपयोग करके जीवन रक्षक आवश्यक दवाएं खरीदने और उन्हें मरीजों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में दवाओं की कमी न हो, इसके लिए कदम उठाए गए हैं।

केएसएमएससीएल के बैंक खाते में उपलब्ध धनराशि से आवश्यक दवाओं की खरीद और उपयोग के लिए अस्थायी अनुमति दे दी गई है और सभी स्वास्थ्य संस्थानों को अनुदान जारी कर दिया गया है। मरीजों को मुफ्त में दवाएं वितरित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। कुश्तगी तालुक के सरकारी अस्पताल को केकेआरडीबी अनुदान के तहत उपलब्ध कराई गई सीटी स्कैन सुविधा चालू है। यह सुविधा गरीब मरीजों को नि:शुल्क प्रदान की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि ऑपरेटरों की कमी से बचने के लिए स्कैन विभाग में तकनीशियनों द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। कुश्तगी में एक मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया गया है और अस्पताल के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति और उपकरणों की व्यवस्था की जा रही है।

रियल एस्टेट कारोबारी की हत्या के मामले में दो नाबालिगों समेत आठ गिरफ्तार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। बेंगलूरु के बाहरी इलाके में एक रियल एस्टेट कारोबारी के अपहरण और हत्या के मामले में दो नाबालिगों सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान आनेकल तालुक के होन्नाकलासापुरा गांव के निवासी गोपाल उर्फ गोपी के रूप में हुई है। उसकी उम्र 30-40 वर्ष के बीच थी। वह रियल एस्टेट और वित्तीय कारोबार से जुड़ा हुआ था।

पुलिस के अनुसार, इस संबंध में पुलिस ने मोहन बाबू नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसे इस अपराध का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है। मोहन बाबू का मानना था कि गोपाल ने उसके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने के लिए काला जादू किया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, हमने गोपाल के अपहरण और हत्या के सिलसिले में आठ लोगों को कृष्णागिरी (तमिलनाडु) स्थित उनके ठिकाने से पकड़ा है। इनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं। इस साजिश में शामिल अन्य साथियों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस मामले की जांच वर्तमान में आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) की टीम द्वारा की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, रविवार को गोपाल और उसके मित्र सतीश, अत्तिबेले से आनेकल की ओर कार में यात्रा कर रहे थे। घटना आनेकल तालुक में कर्पूर गेट के पास हुई। अपहरण की योजना बनाने वाले हमलावरों ने कथित तौर पर कार को रोकने के लिए उसे एक अन्य वाहन से टक्कर मारी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बदमाशों ने कथित तौर पर गोपाल पर एक पदार्थ छिड़का और उसे अगवा कर लिया। इसके बाद वे दूसरी कार में बैठकर मौके से फरार हो गए।

उन्होंने कहा कि अपहर्ताओं ने सतीश पर भी वैसा ही पदार्थ छिड़का था लेकिन वह किसी तरह गोपाल के परिवार वालों को सूचना देने में सफल रहे। अधिकारी ने कहा, ''प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला कि गोपाल और मोहन दोनों चिक्कमगलूरु जिले के कलासपुरा गांव के रहने वाले थे और लगभग 10-12 वर्षों से उनके बीच अनबन थी।'' अधिकारी ने बताया कि बाद में गोपाल ने इसी क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर दिया था जिससे दोनों के बीच शत्रुता पैदा हो गई क्योंकि मोहन को लगा कि वह उसके व्यवसाय में एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी बन रहा है। गोपाल का शव सोमवार सुबह पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के होसुर में बरामद किया गया।

कुमार पर्वत ट्रेक की अवधि बढ़ाने के कदम : ईश्वर बी खंड्रे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। वन मंत्री ईश्वर बी खांड्रे ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा कि सुब्रह्मण्य से कुमार पर्वत तक की पदयात्रा वर्तमान में सुबह 6 बजे के बजाय सुबह 5.30 बजे शुरू की जाए। गुरुवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान, सुलिया विधानसभा क्षेत्र के सांसद भागीरथी मुरली ने कहा कि सुब्रह्मण्य से कुमार पर्वत तक की पहले से निर्धारित ट्रेकिंग के समय में बदलाव से ट्रेकर्स को असुविधा हुई है। इसलिए, वर्तमान में निर्धारित ट्रेकिंग के समय की समीक्षा की जानी चाहिए और इसे पहले की तरह ही तय किया जाना चाहिए।

उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने निष्कर्ष निकाला कि सुरक्षा व्यवस्था के बिना वन्यजीव अभ्यारण्य में रहना उचित नहीं है। चूंकि वहां मानव-वन्यजीव संघर्ष की समस्या बहुत अधिक है, इसलिए ट्रेकर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और अभ्यारण्य के भीतर उचित बुनियादी ढांचे की कमी के कारण तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार, अभ्यारण्य के भीतर रात्रि प्रवास अनिवार्य है। अतः, वर्ष 2024-25 से यह सुझाव दिया गया है कि सुब्रह्मण्य-कुमार पर्वत की 24 किलोमीटर लंबी ट्रेक सुबह 6 बजे शुरू होकर उसी दिन शाम 6 बजे समाप्त होगी।

उन्होंने बताया कि ट्रेकर्स के हित में, सुब्रह्मण्य-कुमार पर्वत-सुब्रह्मण्य ट्रेकिंग मार्ग, जिसकी कुल दूरी 24 किमी है, को घटाकर 20 किमी कर दिया गया है, यानी सुब्रह्मण्य-शेषपर्वत-सुब्रह्मण्य, और इसकी अवधि 12 घंटे तक सीमित कर दी गई है, जिससे उन्हें समय पर लौटने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सदस्यों के अनुरोध पर, अधिकारियों को सुबह 5:30 बजे से ट्रेकिंग शुरू करने के लिए उचित निर्देश दिए जाएंगे।

इसी बीच, विपक्ष के नेता आर. अशोक ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया कि सफारी पर प्रतिबंध लगाना सही कदम नहीं है। सफारी सिर्फ इसी तक सीमित नहीं है। बंदीपुर में मानव-पशु संघर्ष बढ़ने के कारण दो लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्होंने कहा कि बाघों के बढ़ते हमलों के कारण सफारी पर प्रतिबंध लगाया गया है। वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने विधानसभा को बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई वन्यजीव परिषद की बैठक में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर सफारी को फिर से शुरू कर दिया गया है।

साइबर अपराधों पर अंकुश के लिए 43 नए साइबर पुलिस स्टेशन बनेंगे : डॉ. जी परमेश्वर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य में 82,960 साइबर अपराध दर्ज किए गए हैं और साइबर अपराधों को रोकने के लिए राज्य में 43 साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। विधान परिषद सत्र के दौरान सदस्य गोविन्दराजु द्वारा एक बिंदु की पहचान के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि 2021 में 8,396 साइबर अपराध के मामले, 2022 में 12,920, 2023 में 22,255, 2024 में 22,483, 2025 में 14,899 मामले दर्ज किए गए और फरवरी 2026 के अंत तक 2007 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए थे।

राज्य पुलिस विभाग बेंगलूरु शहर में विशेष साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जो भारत में अपनी तरह का पहला स्टेशन है। इंटरनेट और मोबाइल फोन के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी के मामलों की त्वरित जांच करने और प्रतिदिन दर्ज होने वाले मामलों की छानबीन करने के लिए राज्य में डीजीपी साइबर कमांड का पद सृजित किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी साइबर अपराध पुलिस स्टेशन सीधे कार्य रिपोर्ट जमा करके अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और इस कदम से साइबर अपराधों की जांच में तेजी आएगी।

साइबर अपराधों के लिए एक अलग अदालत बनाई गई है। प्रत्येक साइबर स्टेशन में साइबर अपराधों से संबंधित मामलों की जांच के लिए पुलिस इंस्पेक्टर के पदों को अपग्रेड करके डीएसपी/एसीपी के पद कर दिए गए हैं। डिजिटल गिरफ्तारी और साइबर अपराध के मामलों में आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

दक्षिण पश्चिम रेलवे

ई-निविदा सूचना सं: SG-SWR-PROJUBL-KAVACH-BLD दिनांक: 09.03.2026

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित करते हैं:

कार्य का नाम	अनुमानित लागत
प्रस्तावित एक प्रोजेक्ट स्टोर शेड का निर्माण और दूसरे स्टोर का सुधारण के तहत विस्तार कार्य।	रु. 3,37,80,472.45

निविदाओं जमा करने की अंतिम तिथि: 06.04.2026, 11:30 बजे तक

विवरण के लिए लॉग ऑन करें www.ireps.gov.in में

उप मुख्य सिग्नल और दूरसंचार इंजीनियर/परियोजना/हुबली

PUB/990/AAMO/PRB/SWR/2025-26

रेलओन ऐप डाउनलोड करें। रेलओन इंडियन रेलवे का ऑल-इन-वन रेलवे ऐप है। पैसेंजर अपनी उंगलियों पर आरक्षित टिकट, अनारक्षित टिकट, प्लेटफ़ॉर्म टिकट और सीज़न पास बुक कर सकते हैं, पीएनएर स्थिती परिशीलन कर सकते हैं, खाना ऑर्डर कर सकते हैं और कई दूसरी सेवाओं को एक्सेस कर सकते हैं। रेलओन ऐप से अनारक्षित टिकट बुक करने के लिए डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करें और 3% तक छूट का फ़ायदा उठाएँ।

South Western Railway - SWR | SWRRLY | SWRAILWAYHQ | sw_railways

पीएम-किसान की 22वीं किस्त आज हस्तांतरित होगी

कर्नाटक के 41.40 लाख किसानों को लाभ मिलेगा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (पीएम-किसान) के तहत वित्तीय सहायता हस्तांतरण कार्यक्रम की 22वीं किस्त शुरू की गई है। प्रधानमंत्री जी 13 मार्च को शाम 5 बजे ज्योति-बिम्मु अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र, खानपुर, गुवाहाटी से यह अनुदान राशि जारी करेंगे। इस दिन को पूरे देश में प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राज्य के सभी जिला और तालुका केंद्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को देखने की व्यवस्था की गई है।यह योजना उन सभी पात्र किसान परिवारों पर लागू होती है जिनके पास कृषि योग्य भूमि है और जिनका नाम 1 फरवरी 2019 तक भूमि अभिलेखों में दर्ज है। पात्र किसान परिवार को कृषि गतिविधियों के रखरखाव के लिए प्रतिवर्ष कुल 6,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि किसानों के खातों में 2,000 रुपये की तीन किस्तों में, हर चार महीने में एक बार, सीधे नकद हस्तांतरण के माध्यम से जमा की जाएगी। इस 22वीं किस्त में, केंद्र सरकार की ओर से कुल 828.02 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता कर्नाटक राज्य के 41,40,106 लाभार्थियों तक सीधे नकद हस्तांतरण के माध्यम से पहुंचेगी। इस वित्तीय सहायता से किसानों को अपनी कृषि उपज बढ़ाने और बेहतर कृषि उपकरणों का उपयोग करने में मदद मिलेगी।

इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल पर परीक्षण किया

बेंगलूरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने तमिलनाडु के महेंद्रगिरि स्थित अपने प्रणोदन परिसर में नोजल सुरक्षा प्रणाली और बहु-तत्व इग्नाइटर का इस्तेमाल करते हुए 22 टन थ्रस्ट स्तर पर अपने क्रायोजेनिक इंजन (सीई20) का समुद्र तल पर सफलतापूर्वक परीक्षण (हॉट टेस्ट) किया है। इससे पहले, नोजल सुरक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए समुद्र तल परीक्षण 19 टन थ्रस्ट स्तर पर किए जा रहे थे। सीई20 क्रायोजेनिक 'इंजन लॉन्च व्हीकल मार्क-3' (एलवीएम3) के ऊपरी क्रायोजेनिक चरण को शक्ति प्रदान करता है। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर एक पोस्ट में कहा, ''एलवीएम3 वाहन की भार वहन क्षमता को बढ़ाने के लिए, एलवीएम3 के भावी मिशनों को उन्नत सी32 चरण के साथ संचालित करने की योजना है, जिसमें सीई20 इंजन के लिए 22 टन का थ्रस्ट होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए, सीई20 इंजन का उड़ान स्वीकृति परीक्षण भी 22 टन थ्रस्ट स्तर पर आयोजित किया जाना आवश्यक है।'' इसमें कहा गया है, ''इसलिए, वर्तमान परीक्षण (10 मार्च को) ने नोजल सुरक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए 22 टन थ्रस्ट स्तर पर 165 सेकंड की परीक्षण अवधि के साथ इंजन के समुद्र-स्तर परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया।''

मंड्या जिला अदालत को मिली बम की धमकी, तलाशी अभियान के बाद झूठी निकली

मंड्या/दक्षिण भारत। मंड्या जिला अदालत के न्यायाधीश को बृहस्पतिवार को बम की धमकी वाला ईमेल मिला जिससे दहशत फैल गयी और पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। पुलिस के अनुसार, जिला अदालत को दिन में पहले एक ईमेल के माध्यम से बम की धमकी मिली थी जिसके बाद अधिकारियों ने तुरंत परिसर को खाली करा लिया। अदालती कार्यवाही रोक दी गई और वकीलों, न्यायाधीशों, कर्मचारियों और वादी को तुरंत परिसर खाली करने के लिए कहा गया।

पुलिस की टीम बम निरोधक दस्ते और दमकल कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचीं और अदालत परिसर का गहन निरीक्षण शुरू किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गंगाधर स्वामी सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद थे और उन्होंने तलाशी अभियान की निगरानी की। पुलिस ने बाद में कहा कि बम की धमकी झूठी प्रतीत होती है।

वकीलों ने कहा कि 16 फरवरी को भी इसी तरह की ईमेल भेजकर धमकी दी गयी थी और उन्होंने इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति पर चिंता व्यक्त की। पुलिस ने बताया कि इस तरह के कृत्यों में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।

दक्षिण पश्चिम रेलवे

निविदा सूचना सं: 09/2025, दिनांक: 10.03.2026

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित कार्य के लिए केवल आईआरईपीएस माध्यम से ई-निविदाएं आमंत्रित करते है: निविदा समापन होने का समय: 10:30 बजे

क्र.सं.	निविदा संख्या	संक्षिप्त विवरण	मात्रा	निविदा तारीख
01	33261030	संपूर्ण कॉयल फियट बोगी के लिए सेकेंडरी लाटेरल डैम्पर	1372 नं.	26.03.2026
02	33251264	सीबीसी कप्लर के लिए मैन्युअल अन-कप्लिंग डिवाईज़ एसेम्बली	233 नं.	30.03.2026
03	33261047	जेनरेटर कार साईड 1 (आऊटर) के लिए सेकेंडरी स्प्रिंग	92 नं.	31.03.2026
04	33267034	फियट ड्रॉइंग नं. 7247488001 के तहत एक्सल बॉक्स पैवट बुश	19019 नं.	31.03.2026
05	33251258	सी.बी.सी. कप्लर बॉडी के लिए नक्कल	419 नं.	06.04.2026
06	33261025	फिटड ड्राइंग तहत लैटरल बम्प स्टॉप	7263 नं.	09.04.2026
07	33261040ए	एलएचबी का फियट बोगी के लिए बॉल जॉइंट रोल लिंक	21849 नं.	09.04.2026
08	33251330ए	नॉन एसी एलएचबी के लिए सेकेंडरी वर्टिक डैम्पर	4412 नं.	14.04.2026
09	33261049	जेनरेटर कार के लिए सेकेंडरी स्प्रिंग	171 नं.	20.04.2026
10	33261033	सभी प्रकार के एलएचबी कोच के लिए यॉ डैम्पर	1628 नं.	23.04.2026

सूचना सं. 07/2026 के निविदा सं. 46261064 के लिए अंतिम तारीख 25.03.2026 से 18.03.2026 को बदल गया है।

सूचना सं. 07/2026 के निविदा सं. 45265003 के लिए अंतिम तारीख 05.03.2026 से 25.03.2026 को बदल गया है।

सूचना सं. 04/2026 के निविदा सं. 65255010 के लिए अंतिम तारीख 18.03.2026 से 06.04.2026 को बदल गया है। 09.03.2026 को जारी किया गया शुद्धिपत्र-2 नोट किया जाए।

विवरण के लिए लॉग ऑन करें www.ireps.gov.in में

PUB/991/AAMO/PRB/SWR/2024-25 प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक, हुबली

रेलओन ऐप डाउनलोड करें। रेलओन इंडियन रेलवे का ऑल-इन-वन रेलवे ऐप है। पैसेंजर अपनी उंगलियों पर आरक्षित टिकट, अनारक्षित टिकट, प्लेटफ़ॉर्म टिकट और सीज़न पास बुक कर सकते हैं, पीएनएर स्थिती परिशीलन कर सकते हैं, खाना ऑर्डर कर सकते हैं और कई दूसरी सेवाओं को एक्सेस कर सकते हैं। रेलओन ऐप से अनारक्षित टिकट बुक करने के लिए डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करें और 3% तक छूट का फ़ायदा उठाएँ।

South Western Railway - SWR | SWRRLY | SWRRLY

भारत सरकार
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
त्वरित कॉर्पोरेट समापन प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस),
आई.आई.सी.ए. बिल्डिंग, 7वीं मंज़िल,
प्लाट झ-6,7,8, से.-5, आई.एम.टी. मानेसर,
गुड़गाँव, हरियाणा - 122050.
ईमेल: roc.cpace@mca.gov.in

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Corporate Affairs
Centre for Processing Accelerated Corporate Exit (C-PACE)
IICA Building, 7th Floor,
Plot P-6,7,8, Sector-5, IMT Manesar,
Gurgaon, Haryana - 122050.
Email: roc.cpace@mca.gov.in

प्रारूप संख्या एसटीके-6 सार्वजनिक सूचना

कंपनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में

सार्वजनिक नोटिस : ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2025-26/2139 दिनांक : 06/03/2026

संदर्भ:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (70) कंपनियों के नाम कर्नाटक राज्य से हटाने के मामले में:

S NO	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AC1428053	U62011KA2023FTC170932	गोहीबे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
2	AC1459853	U46594KA2023PTC179187	प्राइम पीईबी प्राइवेट लिमिटेड
3	AC1356762	U72900KA2021PTC148858	प्रिसिजन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
4	AC1264167	U62090KA2024FTC190627	एर्गोनेक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
5	AC1745881	U73100KA2023PTC180022	स्पैक मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
6	AC1541709	U74101KA2025PTC202393	मनरिका लाइफस्टाइल एंड फैशन प्राइवेट लिमिटेड
7	AC2321064	U74999KA2012PTC067100	समरुद साइंस एंड हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
8	AC2328035	U70200KA2018PTC109515	रूबिक्स कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
9	AC2308308	U74999KA2019PTC129039	अंतरिक्ष लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
10	AC2313662	U35105KA2025PTC206096	बेलनोवा कैनाकट्टी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
11	AC2323883	U62011KA2024PTC189451	ब्लिंक42 टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
12	AC1651807	U15490KA2019PTC123804	अल्ट्रिक्राक्षण कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
13	AC2513241	U62013KA2023PTC172964	सैलाक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
14	AC2333898	U51101KA2012PTC065574	गॉड्ज इम्पेक्स ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
15	AC2331429	U72900KA2021PTC149926	आईईडीटेक नाइन प्राइवेट लिमिटेड
16	AC2338085	U60220KA2016PTC093187	ओयेसवा प्राइवेट लिमिटेड
17	AC2257252	U72900KA2020PTC142123	ऑगबिज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
18	AC2343773	U74900KA2015PTC081532	रियललेक्स सिनर्जीज़ प्राइवेट लिमिटेड
19	AC2333362	U66190KA2023PTC173630	श्री लक्ष्मी बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
20	AC1672364	U74999KA2016PTC094422	अबंडेंट प्रमोशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
21	AC2493556	U72200KA2013PTC068518	शेनवी सॉफ्टवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
22	AC2355138	U64202KA2002PTC030839	एडीआई 3डी स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड
23	AC2347108	U72900KA2017PTC102773	कर्माकी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
24	AC2369638	U74999KA2018PTC111061	कसेट्टी पावर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
25	AC2364085	U47213KA2022PTC157673	नेक्ससनैस्ट प्राइवेट लिमिटेड
26	AC2364646	U72200KA2001PTC029307	फोरसी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
27	AC2358052	U62099KA2024PTC187222	योज एआई प्राइवेट लिमिटेड
28	AC2359866	U74110KA2015PTC084975	अनन्या दृष्टि सस्टेनेबल कम्युनिटीज प्राइवेट लिमिटेड
29	AC2518735	U51909KA2020OPC140682	नाइट स्किन (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
30	AC2503963	U67110KA2023PTC170032	एआरबीकॉव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
31	AC2308212	U72900KA2022PTC158372	साइबर सुप्रीमो प्राइवेट लिमिटेड
32	AC2399236	U72200KA2016PTC086312	ईक्यूट्राइब सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
33	AC2394003	U74999KA2019PTC121377	एकत्वा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
34	AC2398612	U80300KA2018PTC110227	श्रीशा ट्रांसफॉर्मिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
35	AC2401306	U86909KA2023PTC171976	आयुर्वर्स वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड
36	AC2382925	U82990KA2024PTC192993	पर्पडिजी मीडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
37	AC2493735	U51900KA1995PTC018215	मणिपाल कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
38	AC2391496	U82990KA2023OPC179498	सेल्समाटो एडवाइजरी (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
39	AC2294075	U55100KA2016PTC093407	जूजी प्राइवेट लिमिटेड
40	AC2383071	U62099KA2023OPC173041	सिनाबी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
41	AC2124613	U72900KA2017PTC105523	ऑंटारियो असिस्टेंट्स डेस्क प्राइवेट लिमिटेड
42	AC2412937	U74999KA2020PTC135248	श्रीमान कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
43	AC2291410	U72501KA2022PTC158220	देवट्रे प्राइवेट लिमिटेड
44	AC2421522	U62013KA2024PTC189916	रेडिटियो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
45	AC2419759	U72900KA2022PTC164606	लायज़न बीपीएम प्राइवेट लिमिटेड
46	AC2418726	U62099KA2025PTC211018	ज़ेल कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
47	AC2441664	U52100KA2021PTC155813	बरकत क्लोदिंग प्राइवेट लिमिटेड
48	AC2441657	U80902KA2022OPC167111	गिरिजा कोचिंग एंड कंसल्टिंग सर्विसेज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
49	AC2484932	U62099KA2025OPC197917	न्युआन्सिफाई इनोवेशंस (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
50	AC2445415	U72501KA2019PTC124832	पिकटेल्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
51	AC2468920	U62011KA2025PTC201398	डीपजिप एआई प्राइवेट लिमिटेड
52	AC2463914	U58202KA2024OPC192780	वन6वन फ्यूजन टेक्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
53	AC2466160	U29297KA1991PTC011753	एमकॉन सरफेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
54	AC2472513	U62099KA2024PTC194031	आरएनएवी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
55	AC2452725	U63030KA2017PTC143847	टेकव्हील्स मोबिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
56	AC2090852	U25200KA2012PTC063403	लोटस पॉलीफाइबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
57	AC2135364	U72200KA2015PTC085046	कोरेली सिस्टम्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
58	AC2170813	U74999KA2020PTC139498	इंटेलिविस्टा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
59	AC2285757	U85100KA2018PTC119395	एलवाईएचटी योगशाला प्राइवेट लिमिटेड
60	AC2171998	U72900KA2019PTC126892	खेत्रा एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड
61	AC2282593	U72200KA2008PTC045073	विशारद कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
62	AC2340307	U74210KA2010PTC053271	ऑरा डिजाइन स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड
63	AC2210299	U62091KA2023PTC172476	एन्कोइट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
64	AC2237474	U24233KA2011PTC058179	अंगूर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
65	AC2234374	U72900KA2021OPC146510	डाटाब्रिज देवहब (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
66	AC2244955	U55109KA2025PTC208065	सीविंक स्टेज प्राइवेट लिमिटेड
67	AC2248819	U67100KA2021FTC144409	असेंबली पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
68	AC2254828	U74999KA2020PTC131275	विरुपा एसेंशियल्स प्राइवेट लिमिटेड
69	AC2272635	U58110KA2024OPC192107	क्लिनिबाइट्स इन्फो रिसर्च एंड कंसल्टिंग (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
70	AC2336073	U72200KA2022OPC161457	ग्रीनस्ट्राइप्स एग्री-आईओटी (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कंपनियों के नाम कंपनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कंपनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कंपनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कंपनी ने निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कंपनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अत: कंपनी रजिस्ट्रार से अपना / अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कंपनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कंपनियों के नामों को कंपनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कंपनी को कंपनी रजिस्ट्रार से कंपनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

इरकन तिर्की
उप - पंजीयक
त्वरित कॉर्पोरेट समापन प्रसंस्करण केंद्र

CBC 07123/11/0767/2526

केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं में मिलने वाली राशि का समयसीमा में उपयोग हो : शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं में मिलने वाली राशि का तय समयसीमा के भीतर उपयोग किया जाए ताकि राज्य को केन्द्र से निधि हस्तांतरण सतत रूप से सुनिश्चित हो। शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में केन्द्र सहायता प्राप्त योजनाओं के संबंध में बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं राज्य के सर्वांगीण विकास और महिला, युवा, किसान, मजदूर सहित सभी वर्गों के उत्थान का प्रमुख माध्यम हैं और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी सुधार में इन योजनाओं की बड़ी भूमिका है।

बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रगति तथा लाभार्थियों तक पहुंच की स्थिति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को निरंतर निगरानी के निर्देश दिए।

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन), चिकित्सा शिक्षा, स्वायत्त शासन, स्कूल शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, समेकित बाल विकास सेवाएं विभागों के अंतर्गत संचालित विभिन्न केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं की वित्तीय प्रगति के संबंध में अवगत कराया।

शिक्षा मंत्री दिलावर ने आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश की लॉटरी जारी की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बृहस्पतिवार को शैक्षिक सत्र 202627 के लिए शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश की ऑनलाइन लॉटरी जारी की। 'शिक्षा संकुल' में आयोजित कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़ते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि आरटीई के तहत प्रवेश को पारदर्शी एवं व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा रहा है, जिससे शिक्षा के अधिकार का लाभ समाज के वंचित वर्गों तक पहुंच सके। इस मौके पर राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त अनुपमा जोरवाल तथा निदेशक प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट भी कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े।

जोरवाल ने बताया कि इस वर्ष आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए छह लाख 25 हजार 146 विद्यार्थियों ने आवेदन किया। उन्होंने बताया कि इनमें तीन

लाख 29 हजार 165 बालक, दो लाख 95 हजार 970 बालिकाएं तथा 11 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। जोरवाल ने बताया कि अभिभावकों को प्रवेश के लिए अधिकतम पांच विद्यालयों का चयन करने का विकल्प दिया गया था, जिसके कारण 19 लाख 92 हजार 357 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए।

उन्होंने बताया कि आवेदनों के आधार पर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से विद्यार्थियों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया गया है, जिसके आधार पर आगामी चरणों में विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि अभिभावक 16 मार्च तक विद्यालय चयन क्रम (चॉइस फिलिंग) में परिवर्तन कर सकेंगे। इसके बाद 17 मार्च को प्रथम चरण का विद्यालय आवंटन किया जाएगा। 17 मार्च से 25 मार्च तक दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होगी।

अधिकारियों ने बताया कि सात अप्रैल को द्वितीय चरण का आवंटन किया जाएगा। आवश्यक होने पर अंतिम चरण में शेष रिक्त सीटों के लिए आवंटन आगे बढ़ाया जाएगा। इस चरण में 22 अप्रैल से आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन शुरू होगा।

राहुल गांधी ने भावी चुनौतियों को लेकर सरकार को पहले ही आगाह किया था : अशोक गहलोत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश और केंद्र सरकार को आने वाली चुनौतियों के बारे में बार-बार आगाह किया लेकिन उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। गहलोत ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, राहुल गांधी ने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए समय-समय पर देश और सरकार को भावी चुनौतियों के बारे में आगाह किया है, लेकिन सरकार ने समय पर उन पर ध्यान नहीं दिया जिसका खामियाजा देश को उठाना पड़ा।

उन्होंने कहा कि गांधी ने कई मुद्दों पर पहले ही चेताया था जिसमें कोरोना वायरस का प्रकोप, चीन द्वारा कथित अतिक्रमण, नोटबंदी और जीएसटी का आर्थिक असर, जातिगत जनगणना, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते और पश्चिम एशिया में संकट से भारत पर पड़ने वाला आर्थिक असर शामिल हैं। गहलोत ने कहा, उन (राहुल गांधी) का हर अनुमान समय के साथ सच साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब भारतीय नागरिकों के डेटा की सुरक्षा को लेकर सरकार को लगातार सचेत कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया, चीनी और अमेरिकी कंपनियां भारत का डेटा अपने देशों में अलग-अलग तरीकों से जमा कर रही हैं जिससे भविष्य में इसका दुरुपयोग हो सकता है। दुर्भाग्य से, केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार अब भी इस पर ध्यान नहीं दे रही।

गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी की दूरदर्शी सोच और सबको साथ लेकर चलने के उनके दृष्टिकोण की आज देश को जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के सुझावों पर ध्यान देने के बजाय मोदी सरकार उन पर झूठे आरोप लगाने में लगी हुई है।

राजस्थान में दो-तीन दिन बादल छाए रहने व तापमान में गिरावट का अनुमान

जयपुर। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान में आगामी दो-तीन दिन आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। इसके अनुसार, राज्य में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आगामी 2-3 दिन आंशिक बादल छाए रहने तथा तापमान में 2-3 डिग्री गिरावट होने की संभावना है। वहीं, 14-15 मार्च को अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के जिलों के साथ-साथ गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों तथा आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ बारिश हो सकती है। विभाग के मुताबिक, इसी तरह एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 19-21 मार्च के दौरान सक्रिय होने तथा कहीं-कहीं आंधी चलने और बारिश होने का अनुमान है। इसके मुताबिक, बृहस्पतिवार सुबह तक के 24 घंटों में राज्य में मौसम शुष्क रहा।

उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार कर रही राजस्थान सरकार : भजनलाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं और सरकार ने यहां उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार किया है। मुख्यमंत्री यहां भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) राजस्थान के वार्षिक सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निवेशपरक वातावरण बनाने व नवाचारों को प्रोत्साहन देने सहित विभिन्न ऐसे निर्णय किए हैं जिससे राज्य में उद्योगों के लिए बेहतर वातावरण तैयार हुआ है।

उन्होंने कहा, हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 2047 तक 4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार, शर्मा ने आश्वासन दिया कि राजस्थान में निवेश करने वाले उद्यमियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी तथा उनकी सभी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य में योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को आधार मानकर ग्राम पंचायतों से लेकर नगर निकायों तक के समग्र विकास का खाका तैयार किया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'विकसित भारत 2047' की परिकल्पना दी है जिसे साकार करने में राजस्थान भी अहम भूमिका निभाएगा।

गहलोत ने जयपुर में दांडी मार्च स्मृति पदयात्रा में भाग लिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को जयपुर में दांडी मार्च स्मृति पदयात्रा में भाग लिया। 'भारत सेवा संस्थान' द्वारा आयोजित दांडी मार्च स्मृति पदयात्रा जयपुर में शहीद स्मारक से गांधी वाटिका तक निकाली गई। गहलोत गांधीवादी कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ इसमें शामिल हुए और पैदल चले।

पदयात्रा में शामिल लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा ले रखा था। महात्मा गांधी की वेशभूषा वाला एक व्यक्ति भी इस पदयात्रा में शामिल हुआ।

गहलोत ने कहा, दांडी मार्च केवल नमक कानून के विरुद्ध आंदोलन नहीं था, बल्कि अन्याय और दमनकारी नीतियों के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा अहिंसक प्रतिरोध था।

उन्होंने कहा कि आज जयपुर में 'भारत सेवा संस्थान' द्वारा आयोजित दांडी मार्च स्मृति पदयात्रा में शामिल होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को विनम्रतापूर्वक नमन किया। पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार, लोकतंत्र के समक्ष नयी-नयी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, ऐसे समय में बापू के सत्य, अहिंसा और जनशक्ति के गांधीवादी मूल्यों को फिर से आत्मसात करना ही लोकतांत्रिक आदर्शों को सशक्त करने का सबसे प्रभावी मार्ग है। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया था। इसे दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है।

युवक ने पत्नी, बेटी की हत्या के बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया

जयपुर। जयपुर जिले में एक युवक ने अपनी पत्नी व आठ साल की बेटी की कथित तौर पर हत्या करने के बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार यह यह घटना बुधवार देर रात करीब एक बजे मोखमपुरा थाना क्षेत्र के बिचून गांव में हुई। दूदू के पुलिस उपाधीक्षक दीपक खंडेलवाल ने बताया कि आरोपी सुखजीत ने अपनी पत्नी सरोज देवी (35) पर तलवार से हमला किया और अपनी बेटी वंशिका (आठ) का गला घोंट दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी घर से निकल गया और बाद में मोखमपुरा थाने पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए रखवा दिया। पुलिस के अनुसार टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने कहा कि प्रतीत होता है कि आर्थिक तंगी के कारण व्यक्ति ने ये हत्याएं कीं। आरोपी दिहाड़ी पर काम करता है और परिवार के साथ गांव में अपने घर में रहता था।

पुलिस कांस्टेबल 20 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने बुधवार देर रात को उदयपुर में एक पुलिस कांस्टेबल को 20,000 रुपये की कथित रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार उदयपुर शहर के पुलिस उपाधीक्षक की विशेष टीम में तैनात कांस्टेबल नागेंद्र सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। एसीबी के महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने एक बयान में बताया कि परिवादी ने शिकायत दी थी कि पुलिसकर्मी नागेन्द्र सिंह, शक्ति सिंह, अर्जुन सिंह व अनिल मीणा आए दिन एकलिंगपुरा अंडरपास के पास स्थित उसके कार सर्विस गैराज की जांच कर रहे हैं और उसे डरा धमकाकर परेशान कर रहे हैं। वे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने और परेशान नहीं करने के एवज में 50,000 रुपये मासिक रिश्वत की राशि की मांग कर रहे हैं। बाद में वे 25,000 रुपये की रिश्वत पर मान गए। ब्यूरो की टीम ने शिकायत के सत्यापन के बाद बुधवार रात को आरोपी कांस्टेबल नागेन्द्र सिंह को परिवादी से 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। विशेष टीम के अन्य आरोपी सहायक उपनिरीक्षक शक्ति सिंह, हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह व कांस्टेबल अनिल की तलाश की जा रही है।

जयपुर में हड्डी के कैंसर से पीड़ित बच्चों को 'ग्रोइंग इम्प्लांट' से बार-बार सर्जरी से राहत

जयपुर। बच्चों में होने वाले हड्डी के कैंसर के उपचार के लिए 'ग्रोइंग इम्प्लांट' एक आधुनिक तकनीक के रूप में सामने आया है। हड्डियों के कैंसर के कारण बच्चों की हड्डी का हिस्सा निकालना पड़ता है, लेकिन अब विशेष प्रकार के 'इम्प्लांट' की मदद से हड्डियों की लंबाई को बच्चे की बढ़ती उम्र के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। जयपुर में भगवान महावीर कैंसर अस्पताल के हड्डी शल्य चिकित्सक डॉ. प्रवीण गुप्ता ने बताया कि बच्चों की हड्डियां लगातार बढ़ती रहती हैं, इसलिए सामान्य 'इम्प्लांट' कई बार लंबे समय तक उपयुक्त नहीं रहते। इसी समस्या के समाधान के लिए 'ग्रोइंग इम्प्लांट' विकसित किए गए हैं, जो बच्चे की बढ़ती उम्र के साथ उनकी हड्डियों की लंबाई को संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं। उन्होंने बताया कि 'इम्प्लांट' मुख्य रूप से दो प्रकार से लगाए जाते हैं। पहला वह जिसमें बच्चे के शरीर में लगाए गए 'इम्प्लांट' की लंबाई समय-समय पर ऑपरेशन के माध्यम से बढ़ाई जाती है। आमतौर पर लगभग हर छह महीने में एक छोटा ऑपरेशन कर 'इम्प्लांट' की लंबाई बढ़ाई जाती है, ताकि वह बच्चे की प्राकृतिक वृद्धि के अनुरूप रहे। यह प्रक्रिया आमतौर पर 13 वर्ष की आयु तक जारी रहती है। डॉ. प्रवीण ने बताया कि दूसरा और आधुनिक प्रकार का 'इम्प्लांट' रिमोट कंट्रोल तकनीक पर आधारित होता है। इसमें बार-बार ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती।

प्रदेश में घरेलू रसोई गैस आपूर्ति हेतु पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध, आमजन को घबराने की आवश्यकता नहीं : श्रीनिवास

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति के संबंध में दिए निर्देशों की अनुपालना में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बुधवार को सचिवालय में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षकों, विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों तथा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ वीसी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण हाइब्रिड बैठक ली जिसमें कलेक्टर और एसपी वीसी के माध्यम से जुड़े।

मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार के गत 9 मार्च के एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर के माध्यम से व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है परंतु घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है। उन्होंने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति हेतु प्रदेश में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इस संबंध में घरेलू उपभोक्ताओं को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों में रसोई गैस की निर्बाध एवं नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में संचालित सभी अन्नपूर्णा रसोइयों में भी रसोई गैस का उचित प्रबंध करने हेतु निर्देशित किया।

बैठक में मुख्य सचिव ने घरेलू गैस सिलेंडर आपूर्ति प्रक्रिया की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर निगरानी समितियां बनाने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन समितियों में पुलिस और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों के अधिकारी एवं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। यह कमेटी राज्य एवं जिला स्तर पर मांग एवं आपूर्ति के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर की स्टॉकिंग, आवाजाही एवं वितरण प्रक्रिया की प्रभावी मॉनिटरिंग करेगी तथा घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी एवं अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल के विरुद्ध प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित करेगी।

मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित दिए कि पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 पर एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण आदि के संबंध में आई शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी संज्ञान लेकर कार्रवाई करें। साथ ही, राजस्थान संपर्क की हेल्पलाइन नंबर 181 पर भी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की शिकायत की जा सकेगी। उपभोक्ता मामले विभाग के हेल्पलाइन नंबर 14435 पर भी इस संबंध में शिकायत दर्ज की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी एवं अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल रोकने हेतु जिला एवं राज्य स्तर पर गठित कंट्रोल रूम निरंतर कार्य करेंगे।

सरिस्का अभयारण्य में तीन बाघ शावक का जन्म

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के सरिस्का बाघ अभयारण्य में एक बाघिन ने तीन शावकों को जन्म दिया है जिससे अभयारण्य में बाघों की कुल संख्या 53 हो गई है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि कैमरे में कैद तस्वीरों एवं वीडियो में सरिस्का के अकबरपुर रेंज में बाघिन एसटी-17 को तीन शावकों के साथ देखा गया है। उन्होंने बताया कि बाघिन और उसके शावकों की हलचल और स्वास्थ्य पहली नजर में सामान्य लग रहा है।

अधिकारियों ने कहा कि इस बाघिन एसटी-17 ने पहले भी शावकों को जन्म दिया था और यह उसका दूसरा सफल प्रसव है। उन्होंने कहा कि निगरानी दलों को बाघिन और उसके शावकों की गतिविधि पर पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया गया है। वन मंत्री संजय शर्मा ने इसे राज्य में वन्य जीव संरक्षण के लिए अच्छी खबर बताया।

शर्मा ने कहा, सरिस्का बाघ अभयारण्य से खुश खबरी है। सरिस्का के अकबरपुर रेंज में बाघिन एसटी-17 तीन शावकों की मां बनी हैं। बाघों का बढ़ता कुनबा राजस्थान के वन्यजीव संरक्षण की सफलता की कहानी बयान करता है। राजस्थान सरकार वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। वन्यजीव विशेषज्ञों ने कहा कि बाघिन एसटी-17 का तीन और शावकों की मां बनना इस अभयारण्य में बाघों के संरक्षण एवं पुनर्वास की कोशिशों की सफलता को दिखाता है।

चेटीचण्ड, रामनवमी और महावीर जयंती हमारे महत्वपूर्ण पर्व : देवनानी

जयपुर/दक्षिण भारत। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि आगामी सप्ताह से शुरू होने वाले चेटीचण्ड, रामनवमी और महावीर जयंती के धार्मिक आयोजन हमारे प्रमुख पर्व है। इन अवसरों पर विभिन्न संस्थाओं की ओर से जुलूस निकाले जाएंगे। विभिन्न आयोजन भी होंगे। से में जिला प्रशासन, पुलिस और सभी संबंधित विभाग 16 मार्च तक अपनी तैयारियां पूरी करें। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं की जाए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को अजमेर कलेक्ट्रेट सभागार में चेटीचण्ड, रामनवमी व महावीर जयंती पर्वों को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अजमेर धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक रूप से समृद्ध परम्पराओं को धारण किए हुए है। इन्हीं के अन्तर्गत आगामी चेटीचण्ड पर्व झूलेलाल जयन्ती, रामनवमी पर्व एवं महावीर जयन्ती पर्व पर विशाल शोभायात्राएं एवं जुलूस कार्यक्रम आयोजित होंगे। इनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए समस्त विभागों को अपने दायित्व आगामी 16 मार्च तक पूर्ण करें। उनकी समीक्षा 17 मार्च को मौके पर ही की जाएगी। बैठक में आयोजकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा कर रूट निर्धारित किए गए।

बैठक में देवनानी ने कहा कि प्रशासन द्वारा जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शानदार व्यवस्थाएं की जाए।

असम सरकार ने 5,500 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की

गुवाहाटी/भाषा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बृहस्पतिवार को शिक्षा विभाग के अंतर्गत 5,500 से अधिक उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। शर्मा ने यहां एक आधिकारिक समारोह में औपचारिक रूप से 5,690 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। ये नियुक्तियां प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च शिक्षा क्षेत्र में अनुसंधान स्तर तक के लिए की गई हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस अवसर को असम के शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया, जो पारदर्शी और योग्यता आधारित भर्ती में एक और मील का पत्थर है।

मुख्यमंत्री ने पोस्ट में कहा, इसके साथ ही असम में सरकारी नियुक्तियों की संख्या 1,64,359 हो गई है, जो युवाओं को सशक्त बनाने और शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए असम सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

नेता प्रतिपक्ष और किसी भी सदस्य को नियम के खिलाफ जाकर बोलने का विशेषाधिकार नहीं : बिरला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्होंने निष्पक्षता और नियमों के अनुरूप सदन की कार्यवाही संचालित करने का प्रयास किया है तथा किसी भी सदस्य को नियमों से परे जाकर बोलने का विशेषाधिकार नहीं है।

बिरला ने विपक्ष द्वारा उनके खिलाफ लाए गए संकल्प को सदन द्वारा अस्वीकार किए जाने पर सदस्यों का आभार व्यक्त किया और कहा कि वह पूरी निष्ठा और संवैधानिक मर्यादा के साथ जिम्मेदारी निभाने का प्रयास करेंगे।

बिरला ने कहा, ''यह सदन भारत के 140 करोड़ नागरिकों की संप्रभु इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है...हमेशा यह प्रयास किया है कि सदन के अंदर प्रत्येक सदस्य नियमों और प्रक्रियाओं के तहत अपने मुद्दों पर विचार व्यक्त करें और सभी सदस्यों को इसके लिए पर्याप्त अवसर मिले। यह सदन समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हर उस व्यक्ति की आवाज बने जिसे आज हमारी सबसे अधिक आवश्यकता है।''

उन्होंने कहा, ''मैंने दोनों कार्यकाल में उन सभी माननीय सदस्यों से बोलने का आग्रह किया जिन्होंने सदन में एक बार भी नहीं बोला था। क्योंकि इस सदन में बोलने से लोकतंत्र का संकल्प और मजबूत होता है और सरकार की जवाबदेही भी तय होती है।''

बिरला का कहना था, ''मैंने हमेशा यह प्रयास किया है कि सदन

की कार्यवाही निष्पक्षता, अनुशासन, संतुलन और नियमों के साथ संचालित हो। सदन में सभी को साथ लेकर सामन्जस्य से व्यवस्था एवं कार्यकुशलता बनाये रखना अध्यक्ष का मुख्य कार्य है। मेरा हमेशा यह प्रयास रहता है कि सदन की गरिमा, मर्यादा और प्रतिष्ठा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे।''

लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात का उल्लेख किया कि विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिए जाने के बाद से नैतिक कर्त्तव्य का निर्वहन करते हुए उन्होंने सदन की कार्यवाही से अपने आपको अलग कर लिया था। उन्होंने कहा, ''मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस विश्वास को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए पूरी निष्ठा, निष्पक्षता और संवैधानिक मर्यादा के साथ आगे निभाने का प्रयास करूंगा।''

बिरला ने कहा, ''चर्चा के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता को बोलने से रोका जाता है व उन्हें बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि चाहे सदन के नेता हों, चाहे नेता प्रतिपक्ष हों, मंत्रिगण या अन्य कोई सदस्य हो, सभी को सदन के नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए ही बोलने का अधिकार मिलता है।'' उन्होंने इस बात पर जोर दिया, ''कुछ माननीय सदस्यों का यह मानना है कि प्रतिपक्ष के नेता सदन में कभी भी उठकर किसी भी विषय पर कुछ भी बोल सकते हैं। उन्हें लगता हैं कि यह उनका विशेषाधिकार है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सदन नियमों से चलता है और सदन के कार्य संचालन नियम सदन द्वारा ही बनाए गए हैं।''

बिरला के अनुसार, सदन में जब भी लोक महत्व के किसी विषय पर यदि प्रधानमंत्री या मंत्रियों को वक्तव्य देना होता है, तो उन्हें नियम 372 के तहत अध्यक्ष से पूर्व सम्मति प्राप्त करनी होती है। उन्होंने कहा कि किसी भी सदस्य को नियमों से परे जाकर बोलने का विशेषाधिकार इस सदन में नहीं है।

मोदी सरकार के उपायों से ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति में काफी सुधार आया : भाजपा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राज्यसभा में बृहस्पतिवार को भाजपा सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को रेखांकित करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति में काफी सुधार आया है और अब वहां विभिन प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। भाजपा सदस्यों ने कहा कि न सिर्फ अधिकतर गांव सड़कों से जुड़ गए हैं बल्कि उन्हें बिजली जैसी जरूरी सुविधा भी मुहैया करायी गई है और नक्सल समस्या खत्म होने को है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर उच्च सदन में हुई चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सदस्यों ने पुराने मनरेगा कानून (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) का भी जिक्र किया और कहा कि उस कानून के स्थान पर केंद्र द्वारा लाए गए वीबी जी राम जी कानून में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है।

चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सदस्य बंसीलाल गुर्जर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने के लिए योजना शुरू की थी जिसे मोदी सरकार आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ 25,000 गांव या बस्तियां ही बची हैं जिन्हें भी जल्दी ही सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हजारों गांवों में बिजली नहीं थी और इस सरकार ने लक्ष्य निर्धारित कर उन गांवों को बिजली से जोड़ दिया।

शहीद हवलदार की बेटी की शादी में साथियों ने निभाई पिता की जिम्मेदारी, 14 सैनिकों ने किया कन्यादान

बागपत (उप्र)/भाषा। बागपत जिले के काठा गांव में शहीद हवलदार की बेटी की शादी में उनके साथियों ने भावनात्मक उदाहरण पेश किया। सैनिकों ने न सिर्फ विवाह समारोह की जिम्मेदारी संभाली बल्कि कन्यादान कर पिता की कमी को भी पूरा करने का प्रयास किया। इसका वीडियो हाल में सामने आने के बाद क्षेत्र में इसकी चर्चा हो रही है।

जानकारी के मुताबिक, काठा गांव निवासी हरेंद्र सिंह सेना की 21 जाट रेजीमेंट में हवलदार थे। वर्ष 2020 में अरुणाचल प्रदेश में तैनाती के दौरान एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। उनके परिवार में पत्नी अमृता, बेटी प्राची और दो बेटे हर्षित व अक्षित हैं। हरेंद्र के परिजन ने बृहस्पतिवार को बताया कि उनकी बड़ी बेटी प्राची का विवाह नौ मार्च को शामली जिले के कानियान निवासी शुभम के साथ संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि शादी का निमंत्रण मिलने पर हरेंद्र सिंह के कई साथी सैनिक छुट्टी लेकर गांव पहुंचे और समारोह में सक्रिय भूमिका निभाई।

राहुल ने संसद के मकर द्वार पर पिकनिक मनाई, उन पर कार्रवाई हो: निशिकांत दुबे

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष के दिए आदेश का उल्लंघन करते हुए संसद भवन के मकर द्वार पर ''पिकनिक मनाई'' है। उन्होंने आसन से आग्रह किया कि इसे लेकर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

निशिकांत दुबे ने अपना दावा दोहराया कि राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' में अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस ने पैस दिए थे। उन्होंने नियम 384 और 378 का हवाला देते हुए कहा, ''लोकसभा अध्यक्ष ने आदेश दिया है कि मकर द्वार पर कोई धरना-प्रदर्शन नहीं हो सकता। यह संसद पिकनिक स्थल नहीं है। वह (राहुल) संसद के मकर द्वार पर बैठकर पिकनिक मना रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं।'' दुबे ने कहा कि राहुल गांधी पर कार्रवाई होनी चाहिए। पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने कहा कि आसन ने उनकी बात का संज्ञान ले लिया है।

इस दौरान कांग्रेस के सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद पाल ने सदन की बैठक चार बजकर 50 मिनट पर शाम पांच बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

किसी को नहीं पता राहुल गांधी किस दुनिया में रहते हैं : सिंह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि गांधी को खुद ही नहीं पता कि वह किस दुनिया में रहते हैं।

सिंह ने कांग्रेस पर संसद में मुद्दे उठाकर और फिर बहस में भाग न लेकर भ्रम फैलाने और जनता के पैसे की बर्बादी करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ''किसी को नहीं पता कि राहुल गांधी किस दुनिया में रहते हैं; शायद उन्हें खुद भी नहीं पता। लोगों को शायद उनकी तस्वीर किसी मनोवैज्ञानिक को भेजनी पड़े। शायद कोई मनोवैज्ञानिक ही इसका पता लगा सके। सिंह ने यह टिप्पणी लोकसभा में गांधी की कम उपस्थिति के आरोपों का जिक्र करते हुए की। मंत्री ने कहा, ये लोग देश के दुश्मन हैं, ये लोकतंत्र के दुश्मन हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा में बहस में भाग न लेकर वे गरीबों के पैसे की बर्बादी करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष के प्रस्ताव का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, ''अगर उन्हें कुछ कहना है तो वह सदन चलने दें और वहीं अपने मुद्दे रखें। बुधवार को उन्हें पता था कि यदि मतदान हुआ तो उनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए उन्होंने हंगामा किया और सदन से भाग गए।'' केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे लेकिन आखिरी समय में उससे पीछे हट गए। उन्होंने कहा, आपने देखा कि वे हमारे स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए और अंत में नाटक करने के बाद भाग गए। उनके पास अविश्वास प्रस्ताव को आगे बढ़ाने या मत विभाजन कराने का साहस नहीं था।

बिहार में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें, अधिकारियों ने कहा- रसोई गैस की कोई कमी नहीं

पटना/भाषा। बिहार के कई जिलों में बृहस्पतिवार को गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखी गईं। हालांकि, प्रशासन ने दावा किया कि रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर की कोई कमी नहीं है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार लोगों को एलपीजी सिलेंडर की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए काम कर रही है। पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन एस एम ने कहा कि घरेलू गैस उपभोक्ताओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए पूरा प्रशासनिक तंत्र सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उन्होंने कहा, ''किसी भी तरह की लापरवाही, उदासीनता या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कालाबाजारी, जमाखोरी या अधिक कीमत पर बिक्री की शिकायत मिलने पर संबंधित एजेंसी या व्यक्ति के खिलाफ तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं।'' इस बीच, गैस सिलेंडर आपूर्ति करने वाली एजेंसी के एक प्रतिनिधि के खिलाफ उपभोक्ता की शिकायत पर पटना के पाटलिपुत्र थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिला प्रशासन ने पोस्ट में कहा कि सभी वितरकों और गैस कंपनियों के पास एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने इस मुद्दे पर क्षेत्रीय अधिकारियों, गैस कंपनियों के अधिकारियों, अपर समाहर्ता (आपूर्ति), प्रमंडलीय विशेष पदाधिकारी और सभी अनुमंडल पदाधिकारियों (एसडीओ) के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक निगरानी को मजबूत करने के लिए प्रखंड स्तर पर 28 विशेष धावा दलों का गठन किया गया है। इन टीमों का मुख्य उद्देश्य गैस सिलेंडरों की जमाखोरी रोकना और उपभोक्ताओं तक समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

पवन खेड़ा ने चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए उग्रवादियों से संपर्क करने की कोशिश की : हिमंत

गुवाहाटी/भाषा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बृहस्पतिवार को कहा कि चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए उग्रवादी समूहों से संपर्क करने की कोशिश करने के आरोप में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ तीन से चार प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। शर्मा ने ये आरोप कांग्रेस प्रवक्ता के उस बयान के एक दिन बाद लगाए हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव परिणाम घोषित होने के कुछ ही हफ्तों के भीतर मुख्यमंत्री को उनके कथित भ्रष्टाचार के कारण जेल में डाल दिया जाएगा। शर्मा ने पत्रकारों को बताया, असम में चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए कुछ उग्रवादी संगठनों से संपर्क करने की कोशिश करने के आरोप में पवन खेड़ा के खिलाफ पहले से ही तीन . चार मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, इसलिए, चुनाव के बाद पता चलेगा कि जेल कौन जाएगा। मुझे लगता है कि पवन खेड़ा का आखिरी संबोधन असम की जेल में होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया और संचार अध्यक्ष से तत्काल कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हो सकी।

पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव कर रही केंद्र सरकार : तृणमूल कांग्रेस सांसद

नई दिल्ली/भाषा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद ने बृहस्पतिवार को सरकार पर पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए यह दावा दोहराया कि मनरेगा समेत विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की दो लाख करोड़ रुपए से अधिक राज्य की राशि केंद्र पर बकाया है। उन्होंने वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांग के दूसरे बैच पर, लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए देश में रसोई गैस सिलेंडर की कमी से जुड़ी खबरों का भी जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल में कहा था कि एलपीजी का कोई संकट नहीं है, यदि ऐसा है तो फिर रसोई गैस सिलेंडर के दाम क्यों बढ़ाए गए हैं। उन्होंने कहा, ''केंद्र सरकार उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं मिलने का दावा करके 2022 से बंगाल के बकाया दो लाख करोड़ रुपए नहीं दे रही। राज्य ने उपयोगिता प्रमाणपत्र दे दिया है। लेकिन राज्य का पैसा 'बांग्ला विरोधी' इस सरकार ने नहीं दिया।''

आर एन रवि ने पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ली

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी आर एन रवि ने बृहस्पतिवार को यहां लोक भवन में आयोजित एक समारोह में पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल ने रवि को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी, कोलकाता के महापौर फिरहाद हाकिम और वाम मोर्चा के अध्यक्ष बिमान बोस उपस्थित रहे। हालांकि, विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के किसी नेता ने समारोह में हिस्सा नहीं लिया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत से हुआ।

रवि को लोक भवन में 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया जिसके बाद उन्होंने सरदार पटेल यूनिटी हॉल में शपथ ली। बाद में मुख्यमंत्री ने रवि और उनकी पत्नी का अभिवादन किया और पारंपरिक 'उत्तरीय' (अंगवस्त्र) भेंट कर उनका स्वागत किया। नए राज्यपाल के साथ बातचीत के दौरान ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को संस्कृति की भूमि बताया और कहा कि बंगाल के लोग उन लोगों से प्यार करते हैं जो राज्य से प्यार करते हैं। रवि ने कोलकाता को देश की सांस्कृतिक राजधानी बताया और उल्लेख किया कि ब्रिटिश शासन के दौरान यह भारत की राजधानी के रूप में कार्य कर चुका है। उन्होंने कहा कि वह घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखेंगे। गत पांच मार्च को सीवी आनंद बोस के इस्तीफे के बाद रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इससे पहले वह नगालैंड, मेघालय और तमिलनाडु के राज्यपाल रह चुके हैं।

आगरा : स्कूल बस के टूटे फर्श से नीचे गिरकर पहली कक्षा की छात्रा की मौत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

आगरा (उप्र)/भाषा। आगरा में स्कूल बस के टूटे फर्श से गिरकर पहली कक्षा की एक छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) आदित्य ने बताया कि बुधवार को यह हादसा उस वक्त हुआ जब छुट्टी के बाद स्कूल की बस बच्चों को छोड़ने घर जा रही थी। उन्होंने बताया कि बुधवार को दोपहर करीब तीन बजे बच्चों को लेकर जा रही आरबीएस स्कूल की एक बस के टूटे हुए फर्श से पहली कक्षा की छात्रा नैना नीचे गिर गई और बस का पहिया उसके ऊपर चढ़ गया।

आदित्य ने बताया कि बच्ची के बस से नीचे गिरते ही बस में मौजूद अन्य बच्चों ने शोर मचाया जिसके बाद बस रोकी गई।

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि बच्ची को अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि बस का चालक मौके से फरार हो गया।

नकली संतों का अंत होगा

सपा प्रमुख अखिलेश ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात के बाद कहा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद लिया और कहा कि इस आशीर्वाद से ''नकली संतों का अंत होने जा रहा है।'' स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बातचीत में यादव ने कहा कि वह शंकराचार्य से आशीर्वाद और ज्ञान लेने तथा उनसे कुछ सीखने आए थे।

इस सवाल पर कि क्या शंकराचार्य से वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी कोई आशीर्वाद मिला है, सपा प्रमुख ने कहा, ''हम राजनीतिक लोग हैं। आज के समय पर जहां सोशल मीडिया इतना हावी है, हर व्यक्ति कोई ना कोई राजनीतिक अटकल जताने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन पूजनीय शंकराचार्य से मैं आशीर्वाद लेने आया था।'' यादव ने कहा कि कोई भी शुभ काम शुरू होने से पहले अगर साधु संतों का आशीर्वाद मिल जाए तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा, ''सबसे बड़ी बात है कि शंकराचार्य जी का आशीर्वाद मिलने से नकली संतों का अंत होने जा रहा है।'' ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गौ रक्षा अभियान के तहत बुधवार को लखनऊ पहुंचे थे।

सपा प्रमुख ने आगामी विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों के टिकट कटने की खबर होने का दावा करते हुए कहा, ''सुनने में आ रहा है कि जिले-जिले में बैठकें होने लगी हैं कि किसका टिकट कटेगा और किसका बचेगा। बैठकें हो रही हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि दोनों उपमुख्यमंत्री को बाहर निकालिए और हो सकता है कि जनता के बीच में ये जाएं तो जीतें ही ना।''

इस सवाल पर कि आने वाले समय में बैठकों में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ-साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष भी शामिल होंगे, सपा प्रमुख ने कहा, ''यह लोकतंत्र का सत्यानाश करने वाले लोग हैं। जिलाधिकारी महोदय यह सोचें कि उनके ऊपर भाजपा का जिलाध्यक्ष बैठेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जिलाधिकारी को अपनी नेम प्लेट हटानी पड़ेगी।''

यादव ने रसोई गैस सिलेंडर को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कथित किल्लत के लिए केंद्र सरकार के फैसलों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मस्थली गोरखपुर और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में भी लोगों को रसोई गैस सिलेंडर पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

ईरान के लिए छाती पीट रहे लोग वहीं चले जाएं : पुलिस अधिकारी

सम्भल (उप्र)/भाषा। सम्भल जिले की शहर कोतवाली में अलविदा जुमा की नमाज की तैयारी के सिलसिले में हुई बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी कुलदीप सिंह ने ईरान पर हो रहे अमेरिका और इजराइल के हमले के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को कथित रूप से ईरान जाने की सलाह दी है। सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्हें यह बात कहते सुना जा सकता है। वायरल वीडियो के मुताबिक, सम्भल के प्रभारी पुलिस क्षेत्राधिकारी कुलदीप सिंह ने सम्भल कोतवाली में अलविदा जुमा की नमाज और ईद में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी को लेकर आयोजित एक बैठक में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर तंज किया। वह वीडियो में यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, ''साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान और इजराइल के बीच में, और वो (कई लोग) बीच में अपनी टांग फसाए पड़े हैं। छाती पीट रहे हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप जहाज में बैठकर ईरान चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से।'' पुलिस क्षेत्राधिकारी को यह भी कहते सुना जा सकता है, ''दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है, और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा, तो हम फिर इलाज करेंगे, बहुत बढ़िया वाला।''

भारतीय रेलवे ने ओडिशा से चलने वाली दो विशेष ट्रेनों के नियमितीकरण को मंजूरी दी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भुवनेश्वर/भाषा। भारतीय रेलवे ने भुवनेश्वर-धनबाद और पुरी-पटना विशेष ट्रेनों के नियमितीकरण को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को इस घटनाक्रम की जानकारी दी है।

वैष्णव ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा, जन सुविधा के लिए चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनों के

नियमितीकरण के संबंध में हुई हमारी चर्चा का संदर्भ लें। आपको यह जानकर खुशी होगी कि दोनों विशेष ट्रेनों के नियमितीकरण को मंजूरी दे दी गई है। भुवनेश्वर-धनबाद स्पेशल (02832/02831) अब भुवनेश्वर-धनबाद एक्सप्रेस (18403/18404) के रूप में चलेगी और पुरी-पटना स्पेशल (08439/08440) अब पुरी-पटना एक्सप्रेस (18405/18406) के रूप में चलेगी। भुवनेश्वर-धनबाद एक्सप्रेस प्रतिदिन रात 8.25 बजे भुवनेश्वर से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 11 बजे धनबाद पहुंचेगी। इसकी वापसी यात्रा शाम चार बजे शुरू होगी और ट्रेन अगले दिन सुबह 7.45 बजे ओडिशा की राजधानी पहुंचेगी।

भुवनेश्वर-धनबाद एक्सप्रेस ओडिशा के कटक, ढेंकनाल, तालचेर रोड, अंगुल, रायराखोल, संबलपुर शहर, झारसुगुड़ा और राउरकेला में रुकेगी। साप्ताहिक पुरी-पटना एक्सप्रेस हर शनिवार को दोपहर 2:55 बजे पटना से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 10:45 बजे बिहार की राजधानी पटना पहुंचेगी। वापसी यात्रा में, ट्रेन हर रविवार को दोपहर 1:30 बजे पटना से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 9:45 बजे पुरी पहुंचेगी। यह ओडिशा के खुर्दा रोड, भुवनेश्वर, कटक, जाजपुर, क्योंझर रोड, भद्रक और बालासोर में रुकेगी।

माझी ने ट्रेनों के नियमितीकरण को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री को धन्यवाद दिया।

सुविचार

किसी को उपहार में कीमती चीजें देना आसान है, लेकिन अपना 'समय' देना सबसे कीमती उपहार होता है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

गोबर-गोमूत्र का उपहास क्यों?

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में गोमूत्र के बारे में जो टिप्पणी की, उसमें सत्य नहीं, बल्कि उसका उपहास झलकता है। गोबर और गोमूत्र के बारे में अक्सर ऐसी टिप्पणियां सुनने को मिलती हैं, जिनमें इनके लिए घृणा की अभिव्यक्ति होती है। क्या ये इतनी बुरी चीजें हैं? आजादी के बाद पश्चिम के अंधानुकरण को ही विकास समझ लिया गया था। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि हमारे पास जो कुछ है, वह कचरा है। असल ज्ञान तो पश्चिम के पास ही है! इसी क्रम में गोबर के बारे में दुष्प्रचार किया गया। जिसे मूर्ख साबित करना होता है, उसके बारे में कहा जाता है, 'तुम्हारे दिमाग में तो ... भरा है।' कुछ कंपनियों के प्रतिनिधियों ने किसानों के बीच जाकर गोबर को पिछड़ेपन का प्रतीक बताया और खेती में रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग से होने वाले कथित फायदे बताए। इन पर किसानों ने मोटी रकम खर्च की, आज भी कर रहे हैं। इससे किसानों को कितना फायदा हुआ, यह शोध का विषय हो सकता है। हां, उन कंपनियों को खूब फायदा हुआ। अब इसके दुष्परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। कई रिपोर्टें आ चुकी हैं, जिनमें बताया गया है कि रासायनिक खाद और कीटनाशक हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। जहां इनका बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, वहां कम उम्र में ही लोगों को कैंसर, अल्सर, अपच, डायबिटीज जैसी बीमारियां हो रही हैं। जब तक खेतों में गोबर और गोमूत्र की खाद डाली गई, उपज का स्वाद अच्छा रहा। बहुत लोग इस बात से सहमत होंगे कि पहले गेहूं, चावल, दालों और सब्जियों का जो स्वाद था, उसमें अब बदलाव आ गया है। आप बाज़ार से आलू, मटर जैसी सब्जियां लेकर आएं; साथ ही, अपने घर में कहीं गोबर की खाद से ये सब्जियां उगाकर खाएं। दोनों सब्जियों के स्वाद में अंतर जरूर होगा।

गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। ये शब्द पढ़कर कुछ लोगों को हंसी आ सकती है, लेकिन यह बहुत गहरी बात है। घर में गोबर के लिए गाय का होना जरूरी है। जिस घर में गाय होती है, उसे शुद्ध दूध, दही और घी की प्राप्ति होती है। खेत को शुद्ध एवं सात्विक खाद मिलती है। इससे समृद्धि आती है। गाय उस परिवार के सदस्यों को किसी-न-किसी रूप में व्यस्त रखती है तथा अन्य लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करती है। गाय के बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं। वे किसान के सच्चे साथी होते हैं। जब एक किसान बैलगाड़ी और हल बनवाता है तो कम-से-कम पांच लोगों को रोजगार मिलता है। जिस घर में गाय और बैल होते हैं, वहां लोगों को सुबह जल्दी उठना होता है। उनकी दिनचर्या प्रकृति के अनुकूल रहती है। उन्हें अलार्म लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कई बुजुर्ग किसान यह स्वीकार करते हैं कि जब तक गाय और बैल हमारे घरों में थे, इतनी बेरोजगारी नहीं थी, लड़ाई-झगड़े कम होते थे। जिस दिन खूंटा खाली हुआ, लोगों की दिनचर्या बिगड़ गई। अब वे देर रात तक मोबाइल फोन चलाते हैं। सोशल मीडिया पर जरा-सी बात पर झगड़े हो जाते हैं। आक, धतूरा, नीम और एलोवेरा के साथ गोमूत्र मिलाकर बहुत अच्छा कीटनाशक बनाया जा सकता है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि जो चीजें प्रकृति ने हमारे देश को भरपूर मात्रा में दी हैं, ज्यादातर लोगों को उनकी खूबियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वरिष्ठ राजनेता गोमूत्र के बारे में हल्की टिप्पणी कर रहे हैं। इससे लोगों में क्या संदेश जाएगा? क्या ऐसी टिप्पणी एक विशेष विचारधारा को ताकत नहीं देगी, जो हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति पर हमला करने का मौका ढूंढ़ती रहती है? आयुर्वेद विशेषज्ञ मानते हैं कि गोमूत्र में कई रोगनिवारक गुण होते हैं। उनके पास इसके प्रमाण हैं। किसी व्यक्ति की मर्जी है कि वह इन पर विश्वास करे या न करे, लेकिन जब वह व्यक्ति उच्च शिक्षित हो, वरिष्ठ राजनेता हो और उसके साथ बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ी हों, तो उसे ऐसे विषय पर पर्याप्त अध्ययन करने के बाद ही टिप्पणी करनी चाहिए।

ट्वीटर टॉक

दांडी यात्रा दिवस हमें उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है, जब बापू के नेतृत्व में सत्याग्रहियों ने अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध अदम्य साहस और अहिंसक प्रतिरोध की मिसाल पेश की। 1930 में साबरमती से दांडी तक निकली।

-वसुंधरा राजे

पर्यटन भवन स्थित कार्यालय में बांसवाड़ा-डूंगरपुर के पूर्व सांसद कनकमल कटारा , श्रीमती रूमा देवी , रावणा राजपूत समाज के पदाधिकारियों, विद्याधर नगर विधानसभा के जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्षों तथा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से पधारे नागरिकों से आत्मीय भेंट हुई।

-दिया कुमारी

दांडी मार्च केवल नमक कानून के विरुद्ध आंदोलन नहीं था, बल्कि अन्याय और दमनकारी नीतियों के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा अहिंसक प्रतिरोध था। जयपुर में भारत सेवा संस्थान द्वारा आयोजित दांडी मार्च स्मृति पदयात्रा में शामिल होकर महात्मा गांधी को विनम्र नमन किया।

-अशोक गहलोत

प्रेरक प्रसंग

अन्याय के विरुद्ध

वर्ष 1990 के दशक में चेचन्या में सशस्त्र संघर्ष और नागरिक अत्याचारों के बीच, जर्मन पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता अन्ना पोलिटकोव्स्काया ने वहां के आम लोगों की पीड़ा को उजागर करने का निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि कई परिवारों के सदस्य अचानक गायब हो रहे थे और स्थानीय प्रशासन या सेना इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं देती थी। कई पत्रकार इस क्षेत्र में जाने से डर रहे थे, लेकिन अन्ना ने बिना किसी सुरक्षा गारंटी के सीधे गांवों और शिविरों का दौरा किया, लोगों से साक्षात्कार लिए और घटनाओं का विवरण लिखकर प्रकाशित किया। उनके लेखों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान चेचन्या में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों की ओर खींचा, लेकिन इसके कारण उन्हें लगातार धमकियां और जानलेवा खतरे का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि सत्य की आवाज को दबाने से सच्चाई समाप्त नहीं होती और पत्रकार का कर्तव्य केवल सूचना देना नहीं, बल्कि समाज में अन्याय को उजागर करना भी है। अन्ना पोलिटकोव्स्काया का यह अनुभव आज भी पत्रकारिता और मानवाधिकार कार्य में प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।

सामयिक

हॉर्मुज की घेराबंदी और भारत में गहराता गैस संकट

महेन्द्र तिवारी

मोबाइल : 9989703240

भारत के भीतर इस अंतरराष्ट्रीय संकट का असर सबसे पहले कॉमर्शियल गैस की आपूर्ति पर पड़ा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस की सप्लाई पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने गैस वितरण को चार स्पष्ट श्रेणियों में विभाजित किया है।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा आज एक ऐसे कठिन मोड़ पर खड़ी है जहाँ सरहद पार की जंग हमारे रसोई घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों की दहलीज तक पहुँच गई है। देश के कई राज्यों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में आई अचानक गिरावट ने न केवल होटल और रेस्टोरेंट उद्योग की कमर तोड़ दी है, बल्कि आम नागरिक के मन में भी भविष्य को लेकर एक अनजाना डर पैदा कर दिया है। यह संकट केवल मांग और आपूर्ति का साधारण गणित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक कूटनीति, युद्ध की विभीषिका और भारत की आयात पर अत्यधिक निर्भरता का एक कड़वा परिणाम है। नई दिल्ली के गलियारों से शुरू हुई यह सुगबुगाहट अब पूरे देश में एक बड़े हड़कंप का रूप ले चुकी है, जहाँ उत्तर से दक्षिण तक गैस एजेंसियों के बाहर लगी लंबी कतारें एक गहरे संकट की गवाही दे रही हैं। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को लागू कर दिया है, ताकि जमाखोरी जैसी कुप्रथाओं पर लगाम कसी जा सके और उपलब्ध संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित हो सके। इस पूरे संकट की जड़ें मध्य पूर्व के अशांत भूगोल में धंसी हुई हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्तों में से एक, हॉर्मुज जलमार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। मात्र 167 किलोमीटर लंबा यह जलमार्ग फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और वैश्विक पेट्रोलियम व्यापार की धड़कन माना जाता है। दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत पेट्रोलियम इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। भारत के लिए इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारी अर्थव्यवस्था अपनी जरूरत का 50 प्रतिशत कच्चा तेल और 54 प्रतिशत एलएनजी इसी मार्ग के जरिए मंगाती है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव ने इस मार्ग को युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया है, जिससे टैंकरों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। इसके साथ ही, पिछले दिनों ईरान द्वारा अमेरिका के सहयोगियों कतर, यूएई और कुवैत के ठिकानों पर किए गए ड्रोन हमलों ने आग में घी डालने का काम किया है। विशेष रूप से कतर में एलएनजी प्लांट पर हुए हमलों के बाद उत्पादन रोकना पड़ा है, जो भारत के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि हम अपनी वार्षिक एलएनजी जरूरतों का 40 प्रतिशत हिस्सा अकेले कतर से पूरा करते हैं।

भारत के भीतर इस अंतरराष्ट्रीय संकट का असर सबसे पहले कॉमर्शियल गैस की आपूर्ति पर पड़ा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस की सप्लाई पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने गैस वितरण को चार स्पष्ट श्रेणियों में विभाजित किया है। प्राथमिकता की पहली श्रेणी में घरेलू रसोई गैस (पीएनजी) और सार्वजनिक परिवहन के लिए सीएनजी को रखा गया है, ताकि आम जनता का जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त न हो। दूसरी श्रेणी में खाद कारखानों को रखा गया है, जिन्हें 70 प्रतिशत आपूर्ति दी जा रही है, बशर्ते वे यह प्रमाणित करें कि इस गैस का उपयोग केवल उर्वरक उत्पादन में ही हुआ है। तीसरी श्रेणी में चाय की फैक्ट्रियों जैसे बड़े उद्योगों को रखा गया है, जो 80 प्रतिशत आपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं। सबसे अंतिम और चौथी श्रेणी में छोटे कारखाने, होटल और रेस्टोरेंट शामिल हैं, जिन्हें उनकी पुरानी खपत के आधार पर अधिकतम 80 प्रतिशत सप्लाई का आश्वासन दिया गया है। हालांकि, धरातल पर स्थिति इससे कहीं अधिक गंभीर है और कई छोटे प्रतिष्ठानों को तो पूरी तरह गैस मिलना बंद हो गई है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर में स्थिति विकट हो चली है। यहाँ बुकिंग के कई दिनों बाद भी डिलीवरी नहीं हो रही है और गोरखपुर जैसे क्षेत्रों में गैस एजेंसियों के बाहर एक-एक किलोमीटर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। तेल कंपनियां अपना पूरा ध्यान घरेलू उपभोक्ताओं पर केंद्रित कर रही हैं, जिसके कारण ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों के सामने अपने शटर गिराने की नौबत आ गई है। यही हाल महाराष्ट्र का है, जहाँ मुंबई के लगभग 20 प्रतिशत रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। पुणे में तो संकट इतना गहरा गया है कि नगर निगम को अस्थायी रूप से गैस आधारित शवदाह गृहों को भी बंद करना पड़ा है। 'आहार' जैसे रेस्टोरेंट एसोसिएशनों ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 48 घंटों में आपूर्ति बहाल नहीं हुई, तो आधे से ज्यादा प्रतिष्ठान बंद हो जाएंगे, जिसका सीधा असर उन लाखों कर्मचारियों पर पड़ेगा जो इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल के होटल संचालक शादी के इस व्यस्त सीजन में सिलेंडर न मिलने से हताश हैं, जबकि कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थिति यह है कि कई रेस्टोरेंट्स में केवल कॉफी उपलब्ध है क्योंकि मुख्य भोजन बनाने के लिए गैस ही नहीं बची है।

यह संकट भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक चेतावनी की तरह है। मध्य पूर्व की राजनीतिक अस्थिरता का सीधा असर हमारी रसोई तक पहुँचना यह दर्शाता है कि हम एक नाजुक संतुलन पर टिके हुए हैं। भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए हमें ऊर्जा के स्रोतों में विविधता लानी होगी। अक्षय ऊर्जा, बायोगैस और व्यापक पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार अब केवल विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता बन गए हैं। देश को अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को और अधिक मजबूत करना होगा ताकि किसी भी वैश्विक बाधा की स्थिति में हमारे पास कम से कम 90 दिनों का बैकअप मौजूद हो। इसके साथ ही, घरेलू स्तर पर नेचुरल गैस के उत्पादन को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना हमारा प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। कुल मिलाकर, वर्तमान गैस संकट मध्य पूर्व की उथल-पुथल का एक काला आईना है जो हमें आत्मनिर्भर बनने की सीख दे रहा है। यद्यपि सरकार के प्रयासों और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति से यह संकट आने वाले कुछ हफ्तों में टल सकता है, लेकिन इससे मिलने वाला सबक स्थायी होना चाहिए। रेस्टोरेंट और होटल उद्योग, जो लाखों लोगों को रोजगार देता है और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसे बचाने के लिए त्वरित और ठोस हस्तक्षेप की जरूरत है। साथ ही, आम नागरिक को भी पारदर्शी जानकारी के माध्यम से विश्वास में लेना होगा ताकि समाज में पैनिक न फैले। ऊर्जा विविधीकरण और आत्मनिर्भरता ही वह रास्ता है जो भारत जैसे विशाल और विकासशील देश को भविष्य के वैश्विक झटकों से सुरक्षित रख सकता है। यह समय एकजुट होकर इस अस्थायी संकट का सामना करने और एक स्थायी, सुरक्षित ऊर्जा भविष्य की नींव रखने का है।

नजरिया

अविश्वास प्रस्ताव की राजनीति एवं लोकतांत्रिक मूल्य

ललित गर्ग

मोबाइल : 9811051133

आज आवश्यकता इस बात की है कि संसद की गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा जाए। लोकसभा अध्यक्ष को संसद की निष्पक्षता और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है और इस संस्था के प्रति अनावश्यक राजनीतिक टकराव लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके राजनीतिक दल कितनी परिपक्वता और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।

भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्था संसद है, जहां न केवल कानून बनते हैं बल्कि राष्ट्र की दिशा और दशा पर गंभीर विमर्श भी होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार यही है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी-अपनी भूमिका को लोकतांत्रिक तरीके से जिम्मेदारी, संयम और मर्यादा के साथ निभाएं, यह नितांत अपेक्षित है। किंतु हाल के दिनों में जिस तरह से लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव चर्चा में आया, उसने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया कि क्या विपक्ष वास्तव में संसदीय मर्यादाओं और लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर है या वह केवल स्वार्थ की राजनीतिक करने के लिए ऐसे कदम उठा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना एक गंभीर संसदीय कदम माना जाता है। यह केवल राजनीतिक विरोध का साधन नहीं होता, बल्कि इसके पीछे ठोस तर्क, गंभीर आरोप और व्यापक समर्थन होना अपेक्षित होता है। किंतु जिस प्रकार विपक्ष ने यह प्रस्ताव लाया और बाद में उसकी गंभीरता का अभाव दिखाया, उसने इस पूरी प्रक्रिया को प्रश्नों के घेरे में खड़ा कर दिया। जब यह प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज हुआ तो विपक्ष ने मतदान की मांग तक नहीं की। यदि विपक्ष को अपने प्रस्ताव पर पूरा विश्वास होता और उसे लगता कि वह सदन का समर्थन प्राप्त कर सकता है, तो वह निश्चित रूप से मत विभाजन की मांग करता। लेकिन ऐसा न होना इस तथ्य को ही पुष्ट करता है कि विपक्ष स्वयं भी जानता था कि यह प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में नहीं है।

इससे भी अधिक आश्चर्यजनक स्थिति तब देखने को मिली जब प्रस्ताव पर चर्चा का अवसर आया तो विपक्ष ने स्वयं उस पर चर्चा करने के बजाय पश्चिम एशिया के संकट पर बहस की मांग शुरू कर दी। यह विषय निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, किंतु यदि विपक्ष ने स्वयं लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था तो उसे पहले उसी पर गंभीर चर्चा करनी चाहिए थी। सरकार की ओर से भी यह स्पष्ट किया गया कि वह अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा से पीछे नहीं है, लेकिन संसद की कार्यवाही को नियमों और प्राथमिकताओं के अनुसार चलाना आवश्यक है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह संकेत दिया कि विपक्ष विशेष रूप से कांग्रेस अपने ही प्रस्ताव को लेकर गंभीर नहीं थी। इस अवसर पर ही नहीं, अनेक अवसरों पर उसने गैर-जिम्मेदारी एवं बचकानेपन का अहसास कराया है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वह सरकार की नीतियों की समीक्षा करता है, उसकी गलतियों को उजागर करता है और वैकल्पिक दृष्टि प्रस्तुत करता है। किंतु जब विपक्ष केवल राजनीतिक आरोपों और शोर-शराबे तक सीमित रह जाए तो लोकतांत्रिक विमर्श कमजोर पड़ने लगता है। यहां सत्ता-पक्ष के लिये भी यह गौर करने की बात है कि आखिर विपक्ष को ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी बातों को अनसुना किया जाता है? पक्ष एवं विपक्ष दोनों को ही विश्वास, समन्वय एवं सौहार्द बनाये रखते हुए ही आगे बढ़ना होगा।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का व्यवहार भी कई बार संसदीय मर्यादाओं के संदर्भ में चर्चा का विषय बना है। यह सच है कि विपक्ष के नेता के रूप में उन्हें सरकार की आलोचना करने और अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि संसदीय नियमों और परंपराओं को दरकिनार कर दिया जाए। संसद की कार्यवाही स्पष्ट नियमों और प्रक्रियाओं के अधीन चलती है और इन नियमों का पालन करना हर सांसद की जिम्मेदारी है। बीते कुछ समय से राहुल गांधी संसद के भीतर और बाहर यह आरोप लगाते रहे हैं कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के मामले में प्रधानमंत्री ने समर्पण कर दिया है। इस तरह के आरोपों को उन्होंने कई मंचों पर दोहराया है, किंतु इन दावों के समर्थन में ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए। इसी प्रकार उन्होंने चुनाव आयोग पर भी यह आरोप लगाया कि वह मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण के माध्यम से सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहा है।

इसी संदर्भ में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में विस्तार से यह बताया कि लोकसभा अध्यक्ष पर बोलने का अवसर न देने का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी ने स्वयं कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग नहीं लिया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि संसद के विभिन्न सत्रों के दौरान उनकी उपस्थिति अपेक्षाकृत कम रही है और कई बार महत्वपूर्ण बहसों के दौरान वे विदेश यात्राओं पर रहे। इन तथ्यों को सामने रखते हुए यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि यदि संसद में सक्रिय भागीदारी ही कम होगी तो संसदीय विमर्श को प्रभावी कैसे बनाया जा सकेगा। जहां तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का प्रश्न है, उनका कार्यकाल कई दृष्टियों से उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने सदन की कार्यवाही को संतुलित, संयमित और नियमबद्ध ढंग से संचालित करने का प्रयास किया है। उनके नेतृत्व में संसद की कार्यवाही को अधिक उत्पादक बनाने की दिशा में कई प्रयास किए गए। उन्होंने सांसदों को समयबद्ध तरीके से बोलने का अवसर देने, युवा सांसदों को अधिक सक्रिय करने और संसदीय समितियों की भूमिका को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया।

ओम बिरला की एक बड़ी विशेषता उनका शांत, संयमित और संवादपरक स्वभाव है। वे अक्सर सभी दलों के नेताओं से संवाद स्थापित कर सदन को सुचारुरूप से चलाने की कोशिश करते हैं। कई बार जब सदन में तीखी बहस या हंगामे की स्थिति बनी, तब भी उन्होंने धैर्य और संतुलन के साथ कार्यवाही को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। यही कारण है कि उनके कार्यकाल को संसदीय परंपराओं के सम्मान और लोकतांत्रिक संतुलन के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां लगभग डेढ़ अरब लोगों की आकांक्षाएं, विविधताएं और विचार संसद के माध्यम से अभिव्यक्ति पाते हैं। यह लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह निरंतर संवाद, विमर्श और जवाबदेही की प्रक्रिया है। संसद इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का केंद्रीय मंच है। इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि वहां होने वाली बहसें गंभीर, तथ्यपूर्ण और मर्यादित हों।

आज आवश्यकता इस बात की है कि संसद की गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा जाए। लोकसभा अध्यक्ष को संसद की निष्पक्षता और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है और इस संस्था के प्रति अनावश्यक राजनीतिक टकराव लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके राजनीतिक दल कितनी परिपक्वता और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। यदि विपक्ष अपनी भूमिका को गंभीरता और रचनात्मकता के साथ निभाए और सत्ता पक्ष भी संवाद के लिए खुलेपन का परिचय दे, तो भारतीय लोकतंत्र न केवल मजबूत होगा बल्कि विश्व के सामने एक आदर्श भी प्रस्तुत करेगा। यही वह मार्ग है जो संसद की गरिमा, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रहित-तीनों की रक्षा कर सकता है।

महत्त्वपूर्ण

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company,6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**, (*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- दक्षिण भारत राष्ट्रमत

मांग

झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने भाजपा विधायकों के साथ मिलकर विधानसभा के बजट सत्र के दौरान किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर तख्तियां दिखाईं और विरोध प्रदर्शन किया।

कुंभ मेले की मोनालिसा ने प्रेमी के साथ रहने के लिए मांगी पुलिस की मदद

तिरुवनंतपुरम/भाषा। प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान मशहूर हुई युवती मोनालिसा भोसले ने बुधवार को यहां पुलिस से अपने प्रेमी के साथ रहने और उससे शादी करने के लिए सुरक्षा मांगी है। यहां थंपनूर पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद उसने आरोप लगाया कि उसके पिता उसे जबरदस्ती उसके गृहनगर वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि वह (मोनालिसा) एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में केरल की राजधानी में थी। दिलकश मुस्कान और खूबसूरत आंखों वाली इंदौर की यह लड़की तब मशहूर हुई जब एक 'वर्चुअल कंटेंट क्रिएटर' ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेले में रुद्राक्ष की माला बेचते हुए उसका एक वीडियो साझा किया।

पुलिस के मुताबिक, भोसले और उसका प्रेमी जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, फिल्म के सदस्यों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे और आरोप लगाया कि उसके पिता मर्ज़ी के खिलाफ उसे वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह जोड़ा हाल ही में फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में पास के पूवार पहुंचा था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ''उसने ज़ोर दिया कि वह अपने पिता के साथ नहीं जाएगी और यह साफ़ कर दिया कि वह अपने प्रेमी से शादी करने जा रही है। चूंकि वह बालिग है, इसलिए वह अपनी मर्ज़ी से काम कर सकती है।'' पुलिस अधिकारी ने कहा कि बाद में वह अपने प्रेमी और फिल्म के सदस्यों के साथ चली गई।

शिष्टाचार भेंट

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में जलपान (ब्रेकफास्ट) के निमंत्रण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें अपनी शुभकामनाएं दीं।

खाड़ी क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर विचार-विमर्श करने शहबाज शरीफ सऊदी अरब की यात्रा पर गए

इस्लामाबाद/भाषा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बृहस्पतिवार को सऊदी अरब की संक्षिप्त सरकारी यात्रा पर रवाना हुए। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के रक्षा समझौते के कारण इस यात्रा में पाकिस्तान की भूमिका की परख होगी।दोनों देशों ने पिछले साल सितंबर में एक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे तथा दोनों ने किसी तीसरे देश द्वारा हमला किए जाने की स्थिति में एक-दूसरे की रक्षा करने की प्रतिबद्धता जतायी थी। यह समझौता तब हुआ था जब इजराइल ने कतर में हमास के नेताओं पर हमला किया था।

हालांकि, अमेरिका और इजराइल द्वारा साथ मिलकर ईरान पर हमले शुरू किए जाने के बाद स्थिति बदल गई । ईरान ने खाड़ी देशों में बमबारी करके जवाबी कार्रवाई की।ईरान के साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंधों और भौगोलिक निकटता को देखते हुए, इस बात को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करेगा।

एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के प्रवक्ता मुशरफ जैदी ने कहा था कि पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद के लिए 'जरूरत पड़ने से पहले ही' मौजूद रहेगा।प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के एक बयान में कहा गया है कि सऊदी के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री यह यात्रा कर रहे हैं।

उसने कहा है कि प्रधानमंत्री सऊदी अरब के युवराज से मुलाकात करेंगे तथा भेंटवार्ता के दौरान दोनों 'क्षेत्र में जारी तनाव, क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर विचार-विमर्श करेंगे।''प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा,''यह दौरा कूटनीतिक क्षेत्र में पाकिस्तान की सकारात्मक भूमिका को उजागर करता है और पाकिस्तान इस भूमिका को निभाता रहेगा।''

अलग से, विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंद्राबी ने साप्ताहिक ब्रीफिंग के दौरान इस यात्रा की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री एक दिवसीय सऊदी अरब यात्रा पर रवाना हुए हैं। उन्होंने बताया कि उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार भी प्रधानमंत्री के साथ इस यात्रा पर गए हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि यह यात्रा क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित मामलों पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच चल रहे समन्वय का हिस्सा है।

चीन की संसद का वार्षिक सत्र कई कानूनों को अनुमोदित करने के साथ संपन्न

बीजिंग/भाषा। चीन की संसद का बहुचर्चित वार्षिक सत्र कई कानूनों को मंजूरी देने के साथ बृहस्पतिवार को समाप्त हो गया। इन कानूनों में देश की अर्थव्यवस्था में मंदी पर काबू पाने के लिए नई पंचवर्षीय योजना, रक्षा बजट में वृद्धि और विवादास्पद जातीय कानून शामिल हैं।विवादास्पद जातीय कानून सभी जातीय अल्पसंख्यकों के लिए मंदारिन भाषा को अनिवार्य बनाता है।नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) का वार्षिक सत्र दो सप्ताह से भी कम समय में संपन्न हुआ। एनपीसी को अक्सर रबर-स्टैंप संसद कहा जाता है क्योंकि वह सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) द्वारा अनुमोदित कानूनों पर नियमित रूप से बस मुहर लगाती है।

एनपीसी और शीर्ष सलाहकार निकाय - चीनी पीपुल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस (सीपीपीसीसी) का वार्षिक सत्र मार्च के पहले हफ्ते में शुरू हुआ था जिसमें 5,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।अमेरिका-ईरान युद्ध और चीनी राष्ट्रपति शी चिनपिंग द्वारा किए गए व्यापक सैन्य बदलावों के कारण व्याप्त उथल-पुथल के बीच आयोजित इन दोनों सत्रों ने वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया।

शी जिनपिंग (72) ने दोनों सदनों के सत्र में भाग लिया।इससे पहले, दोनों सत्रों में भाग लेने वाले 240 से अधिक प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए, शी चिनपिंग ने सैन्य अधिकारियों से राजनीतिक निष्ठा बढ़ाने का खुला आह्वान किया, जिसका अर्थ है पार्टी के नेतृत्व का अनुसरण करना।शी चिनपिंग पीएलए और सीपीसी की समग्र उच्च कमान, केंद्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) के प्रमुख भी हैं।जनवरी में पीएलए के सर्वोच्च रैंक वाले जनरल झांग यूक्सिया समेत दो वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को उनके पद से हटाए जाने के बाद शी की यह पहली बैठक है। दोनों सैन्य अधिकारियों को उनके पद से हटाये जाने को हाल के इतिहास में पीएलए में बड़ा बदलाव माना गया, जो निचले स्तर के सैनिकों के लिए झटके जैसा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि छह सदस्यीय सीएमसी के अंतिम बचे जनरल झांग शेंगमिन ने संसद के वर्तमान सत्र में अपने भाषण में सेना से शी चिनपिंग के आदेश का दृढ़तापूर्वक पालन करने का आह्वान किया। एनपीसी का सत्र पांच मार्च को शुरू हुआ, जिसमें शी चिनपिंग के करीबी सहयोगी प्रधानमंत्री ली कियांग ने अपनी सरकार की कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में हाल के वर्षों में पहली बार चीन के जीडीपी लक्ष्य को इस वर्ष के लिए 4.5 से 5 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है।

ममता कुलकर्णी ने प्रशंसकों को दिखाया अपना नया परिवार

मुंबई/एजेन्सी

हिंदी सिनेमा के 90 के दशक की लोकप्रिय अभिनेत्री और मॉडल ममता कुलकर्णी आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। हाल ही में अभिनेत्री लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सीजन-3 शो में गेस्ट के रूप में नजर आईं। इसके साथ ही अभिनेत्री ने 25 सालों के लंबे गैप के बाद टीवी पर वापसी की। ममता कुलकर्णी ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जहां वह प्रशंसकों को नमस्ते करने के साथ वीडियो की शुरुआत करती हैं और लोगों को अपने परिवार से मिलाती हैं। वीडियो में अभिनेत्री अपने घर में बैठी नजर आ रही हैं, जहां उनके बालकनी में कौआ खाना खा रहा है। एक्ट्रेस ने उन्हें दिखाते हुए कहा, अभी हम सब मिलकर सुबह का नाश्ता कर रहे हैं, बस यही मेरी दुनिया है। वीडियो में ममता बाल खोली काले रंग के कपड़े में नजर आ रही हैं। अभिनेत्री के इस पोस्ट पर कुछ ही देर में हजारों व्यू और लाइक्स आ चुके हैं। वहीं, फैंस लगातार कमेंट्स के माध्यम से

एक्ट्रेस के पोस्ट पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जहां एक यूजर लिखता है, आर्यावर्त के ऋषि-मुनि आज से हजारों साल पहले भविष्यवाणी कर चुके थे कि कलयुग में नारी जाति अपने बाल खुले रखेगी। जय सियाराम, वहीं, दूसरे यूजर का कमेंट आता है, आप अच्छी लग रही हैं, हमेशा की तरह। एक और यूजर कमेंट करते हैं, नमस्ते नहीं, जय श्री राम। जय मां भद्रकाली मातेश्वरी नारायणी। योगी हैं आप। नारायण से नाम लो। जय श्री राम। कुछ यूजर कमेंट्स के माध्यम से यह सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या आप अकेली रहती हैं?

बता दें, ममता कुलकर्णी बीते कुछ समय में काफी विवादों में रही हैं। जनवरी 2025 में प्रयागराज महाकुंभ के दौरान वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी थीं लेकिन कुछ ही समय बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर टिप्पणी करने के कारण वो विवादों में आ गईं। इसके बाद किन्नर अखाड़ा ने उन्हें पद से निष्कासित कर दिया। अभिनेत्री दो दशकों से ज्यादा समय से फिल्मी दुनिया से दूर रहीं और अध्यात्म का मार्ग अपनाया। हालांकि, 25 सालों के लंबे गैप के बाद उन्होंने एक बार फिर टीवी पर वापसी की। लाफ्टर शेफ्स में बतौर गेस्ट के रूप में आकर ममता ने अपने फैंस को सरप्राइज दिया।

प्रदर्शन

दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एलपीजी की किल्लत और कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में गुरुवार को नई दिल्ली के झंडेवालान इलाके में जोरदार प्रदर्शन किया।

उपस्थिति

अभिनेत्री कृतिका कामरा और टेलीविजन होस्ट गौरव कपूर शादी के बाद पहली बार एक साथ सार्वजनिक रूप से नजर आए और मुंबई में तस्वीरें खिंचवाईं।

पुरुष की सफलता में महिलाओं का आशीर्वाद जरूरी, गोविंदा का पुराना इंटरव्यू वायरल

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोविंदा अपनी फिल्मों को लेकर काफी चर्चा बटोरते थे और आज वह अपने निजी जीवन को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने साल 1987 में सुनीता आहूजा से शादी की थी, लेकिन अब वह इसी रिश्ते को लेकर सवालों के घेरे में हैं। कभी तलाक की खबरें सामने आती हैं, तो कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अफवाहें जोर पकड़ने लगती हैं। इन सबके बीच गोविंदा का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह पुरुषों की जिंदगी में महिलाओं की अहमियत पर बात करते नजर आ रहे हैं। इस बातचीत में उन्होंने अपनी मां की सीख को याद करते हुए बताया कि किसी भी पुरुष की सफलता में महिलाओं का आशीर्वाद बहुत मायने रखता है।

यह बातचीत उन्होंने लहरें टीवी को दिए एक इंटरव्यू में की थी। इस दौरान गोविंदा कहते हैं, ''मेरा मानना है कि हर पुरुष को अपनी

जिंदगी में मौजूद महिलाओं को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। महिलाओं का आशीर्वाद किसी भी आदमी की जिंदगी को बेहतर बना सकता है। जब किसी व्यक्ति को महिलाओं का समर्थन और दुआ मिलती है, तो उसकी सफलता की राह और भी आसान हो जाती है।''गोविंदा ने कहा, ''मेरी मां हमेशा कहती थीं कि महिलाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं और उनके बिना पुरुष कमजोर हो जाता है। भगवान शिव भी तब तक पूर्ण नहीं माने जाते जब तक उनके साथ देवी शक्ति का साथ न हो। स्त्री और पुरुष दोनों एक-दूसरे के पूरक होते हैं और दोनों का साथ जीवन को संतुलित बनाता है।''अभिनेता ने आगे कहा, ''अगर कोई पुरुष अपनी जिंदगी में महिलाओं का सम्मान करता है और उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ता है तो उसकी सफलता बढ़ जाती है। यह बात सिर्फ पत्नी तक सीमित नहीं है, बल्कि मां, बेटी, दोस्त या किसी परिचित महिला के रूप में भी महिलाओं का सम्मान और आशीर्वाद बेहद जरूरी होता है।'' इस बातचीत के दौरान गोविंदा ने खुद को मां का लाड़ला बेटा बताया। उन्होंने कहा, ''जीवन के शुरुआती दिनों में मेरा सबसे बड़ा सपना अपनी मां के लिए एक सफल बेटा बनना था। अब एक अच्छा पति और पिता बनना है।

भावनाओं में बहकर शो छोड़ना आसान है पर जिम्मेदारी निभाना चुनौती : निक्की तंबोली

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेत्री निक्की तंबोली रियलिटी शो 'द 50' से बाहर हो गई हैं। उन्हें डबल एविक्शन में शो से बाहर कर दिया गया। शो से निकलने के बाद निक्की ने बुधवार को इंस्टाग्राम के जरिए शो में चल रहे संघर्ष और अपनी हालत के बारे में बात की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक नोट लिखा और अपनी भावनाएं व संघर्ष साझा किए। निक्की ने लिखा, कई लोग कह रहे हैं कि जब अरबाज को शो से निकाला गया, तो मुझे भी शो छोड़ देना चाहिए था, लेकिन शो में आने का मतलब जिम्मेदारी और वादा निभाना होता है। भावनाओं में आकर शो छोड़ना आसान लग सकता है पर कमिटमेंट निभाना असली हिम्मत है। निक्की ने लिखा कि जब मेरे भाई का देहांत हुआ था, तब भी मैं अगले दिन 'खतरों के खिलाड़ी' की शूटिंग के लिए गई थी। उन्होंने लिखा, मेरे लिए कमिटमेंट का मतलब यही होता है। भावनाएं सच्ची होती हैं, लेकिन जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। शो ने मुझे हमेशा सम्मान, महत्व और प्राथमिकता दी। कमिटमेंट सिर्फ भावनाओं का नाम नहीं, बल्कि उस हिम्मत का नाम भी है, जब पता होता है कि बाहर लोग आलोचना करेंगे, कहानियां बनाएंगे, फिर भी आप मजबूत रहते हैं। निक्की ने बताया कि शो में जाने से पहले वे डेंगू से ठीक होकर आई थीं। इसलिए ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही थीं। उन्होंने लिखा, कई लोगों ने मेरी परफॉर्मेंस को जज किया, बिना जाने कि मैं डेंगू से ठीक होकर आई थी। शरीर में थकान, कमजोरी और बहुत ज्यादा थकावट थी। छोटी-छोटी चीजें भी भारी लगती थीं, फिर भी मैं हर दिन हिम्मत से शो में गई। उन्होंने कहा कि शो में उनका मुकाबला किसी दूसरे से नहीं बल्कि खुद से था। उन्होंने कहा, मेरा असली मुकाबला किसी से नहीं बल्कि खुद से था।अपनी ताकत, सीमाओं और शरीर की लड़ाई से। सबसे कठिन लड़ाइयां अक्सर दिखाई नहीं देतीं। हर दिन वहां पहुंचना, थकान के बावजूद खड़े रहना और हार न मानना यही मेरी असली चुनौती थी।

फिल्म 'निशानची' में डबल रोल का चला जादू, ऐश्वर्य ठाकरे ने जीता अवॉर्ड

मुंबई/एजेन्सी

फिल्म 'निशानची' से हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने वाले अभिनेता ऐश्वर्य ठाकरे ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। दरअसल, अभिनेता को हाल ही में अपनी डेब्यू फिल्म में शानदार अभिनय के लिए बेस्ट डेब्यू मेल (जूरी) अवॉर्ड मिला। क्राइम ड्रामा फिल्म 'निशानची' साल 2025 में रिलीज हुई थी और इसका निर्देशन अनुराग कश्यप ने किया था। फिल्म में ऐश्वर्य के अलावा, वेदिका पिंटो, मोनिका पंवार, मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब और कुमुद मिश्रा जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म में ऐश्वर्य ठाकरे ने अपने डबल रोल से काफी प्रभावित किया था और उनके इस रोल के लिए काफी सराहना भी मिली थी। यह सम्मान ऐश्वर्य ठाकरे के अभिनय करियर का पहला बड़ा अवॉर्ड है। फिल्म निशानची में उनके

अभिनय को समीक्षकों और दर्शकों दोनों से सराहना मिल रही है, जिससे वह इंडस्ट्री के उभरते हुए कलाकारों में शामिल हो गए हैं।

ऐश्वर्य ने अपनी इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की। उन्होंने फिल्म के निर्देशक अनुराग कश्यप का आभार जताया और कहा कि उनके साथ अपने सिनेमा सफर की शुरुआत करना उनके लिए एक सौभाग्य की बात है।उन्होंने कहा, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मेरा सफर इतने ईमानदार और जीनियस क्रिएटर के साथ शुरू हुआ। अनुराग सर ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे उनके सिनेमा का हिस्सा बनने का मौका दिया।ऐश्वर्य ने अपनी पूरी टीम का भी धन्यवाद किया।

उन्होंने अपने सह-कलाकारों वेदिका पिंटो, मोनिका पंवार, जीशान अय्यूब, कुमुद मिश्रा और विनीत कुमार सिंह सहित पूरी टीम का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनके लिए सिर्फ खुशी का पल नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा, यह अवॉर्ड मेरे लिए सिर्फ खुशी नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। अब मुझे और भी बेहतर काम करना है। अच्छी कहानियां दर्शकों तक पहुंचानी है और खुद को लगातार बेहतर बनाना है। अपने संबोधन के अंत में ऐश्वर्य ठाकरे ने अपनी लिखी हुई एक शायरी भी सुनाई, रास्ते में अपने बनाऊंगा, गलतियां मेरी अब न बढ़ाऊंगा, कामयाबी पाने के बाद भी दुनिया सबको सुनाऊंगा।

वर्षीतप प्रारंभ दिवस पर वर्षीतप आराधकों ने ग्रहण किए सामूहिक प्रत्याख्यान

श्रेयांस पारणा समिति ने किया आयोजन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के मागड़ी रोड स्थित गुरु ज्येष्ठ पुष्कर जैन आराधना केन्द्र में पंडितरत्नश्री ज्ञानमुनिजी, उपप्रवर्तिनीश्री सत्यप्रभाजी के सान्निध्य में आदिनाथ ऋषभदेव भगवान के जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक के पावन पवित्र दिवस पर श्रेयांस पारणा समिति के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में गुरु ज्येष्ठ पुष्कर आराधना केन्द्र में अनेक श्रावक श्राविकाओं ने वर्षीतप प्रारंभ किया तथा प्रत्याख्यान ग्रहण किए। लगभग 400 दिनों तक चलने वाली तेरह महीने की यह वर्षी तप आराधना आगामी वर्ष के अक्षय तृतीया के दिन पूर्णाहुति होगी। श्रेयांस पारणा समिति के चेयरमैन रमेशचंद सियाल एवं सह चेयरमैन मीठालाल लोढ़ा ने सभी श्रद्धालुओं तपस्वियों का स्वागत किया और अक्षय तृतीया पारणा महोत्सव आचार्य पार्श्वचंद्र डॉ एवं एस एस समणी मार्ग के प्रारंभकर्ता पदमचंद्रमुनि के सान्निध्य में त्रिपुरावासिनी के प्रांगण में 400से अधिक पारणा की तैयारियां किए जाने की जानकारी दी। समिति के प्रवक्ता जेके महावीरचंद चोरड़िया ने बताया कि इस अवसर पर 38 उदारमनाओं ने एकांतर पारणा व्यवस्था के वार्षिक सहयोगी बनने की घोषणा की। इस अवसर पर समाज के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

सम्मान

हुब्बल्ली के शांतिनिकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्राचार्या एम. वडिवुकरसी को शिक्षा क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इंडियन फोरम अवॉर्ड्स द्वारा 'विमेन अकादमिक एक्सीलेंस अवॉर्ड-2026' से सम्मानित किया गया। उन्हें यह अवार्ड शिक्षा क्षेत्र में मजबूत नेतृत्व, शैक्षणिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता तथा विद्यार्थियों को उत्कृष्टता की ओर मार्गदर्शन करने के लिए दिया गया है। शांतिनिकेतन मंडल के अध्यक्ष भवरलाल जैन तथा सभी निदेशकों ने प्राचार्य वडिवुकरसी को शुभकामनाएं दी।

बेंगलूरु में पाइपलाइन से आने वाली प्राकृतिक गैस की कोई कमी नहीं है : गेल

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। बेंगलूरु में पाइप वाली प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है और पीएनजी नेटवर्क से जुड़े होटल और उद्योगों को बिना किसी रुकावट के निर्बाध आपूर्ति मिलती रहेगी। गेल गैस लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक (सीजीडी) और कार्यवाहक संजय कुमार सिंह ने गुरुवार को यहां बेंगलूरु चैंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स (बीसीआईसी) द्वारा आयोजित 'प्राकृतिक गैस आपूर्ति दृष्टिकोण और उद्योग की तैयारी' पर एक संवादात्मक सत्र में विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए यह बात कही।

सिंह ने बताया, बेंगलूरु में पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति स्थिर और पूरी तरह नियंत्रण में है। पीएनजी नेटवर्क से जुड़े उद्योगों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपूर्ति में कोई रुकावट नहीं है और व्यावसायिक गतिविधियां निर्बाध रूप से चलती रहेंगी। जो भोजनालय और होटल व्यावसायिक एलपीजी का उपयोग कर रहे हैं और आपूर्ति को लेकर चिंतित हैं, वे उपलब्धता के आधार पर मात्र दो महीनों के भीतर पीएनजी लाइन पर स्विच कर सकते हैं।

बेंगलूरु में एलपीजी की कमी की अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए, सिंह ने आश्वासन दिया कि सरकार ने घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ा दिया है, इसलिए घरेलू एलपीजी उपयोगकर्ता राहत की सांस ले सकते हैं। उन्होंने कहा, हम 'गेल' में अपने पाइपलाइन नेटवर्क का लगातार विस्तार कर रहे हैं और बेंगलूरु शहर में नए पाइपलाइन गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता प्राकृतिक गैस (पीएनजी) का उपयोग शुरू कर सकें, जो न केवल कुशल है बल्कि एक स्वच्छ और अधिक टिकाऊ ऊर्जा समाधान भी है। भारत पूरी तरह से किसी एक अंतरराष्ट्रीय स्रोत पर निर्भर नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक गैस का आयात कई क्षेत्रों से होता है। सिंह ने प्राकृतिक गैस आपूर्ति के बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना का भी उल्लेख किया। अधिसूचना के अनुसार, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं को पिछले छह महीनों में उनकी औसत गैस खपत का 80 प्रतिशत तक प्राप्त होगा, जबकि घरेलू और सीएनजी क्षेत्रों को शत प्रतिशत आपूर्ति मिलती रहेगी। इस उपाय का उद्देश्य वर्तमान वैश्विक आपूर्ति अनिश्चितताओं के दौरान गैस के उपयोग को युक्तिसंगत बनाना और समान वितरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उद्योग अभी भी 80 प्रतिशत सीमा से अधिक खपत कर सकते हैं, लेकिन इस अतिरिक्त उपयोग के लिए अलग मूल्य सीमा के तहत बिल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अस्थायी युक्तिसंगतता मुख्य रूप से अपव्यय को हतोत्साहित करने और निर्बाध आपूर्ति बनाए रखते हुए सभी क्षेत्रों में गैस के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है।

उद्योग प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए, बेंगलूरु चैंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स (बीसीआईसी) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रवि ने कहा, हम उद्योग जगत से सीधे बातचीत करने और बेंगलूरु में एलपीजी और पीएनजी की उपलब्धता से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए गेल की सराहना करते हैं।

राज्य में ईंधन और एलपीजी आपूर्ति :

सरकार की सख्त कार्रवाई : मुनियप्पा

बेंगलूरु। सरकार ने राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की हालिया कमी को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही झूठी और निराधार अफवाहों का गंभीर संज्ञान लिया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री के. एच. मुनियप्पा ने कहा कि जनता को ऐसी अफवाहों से घबराना नहीं चाहिए। गुरुवार को विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान, परिषद के सदस्यों रमेश बाबू, शिवकुमार के, इवान डिसूजा, रामोजी गौड़ा, जगदेव गुट्तेदार और राजेंद्र राजन्ना द्वारा नियम 330 के तहत पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री जी ने कहा कि केंद्र सरकार की जानकारी के अनुसार, पूरे देश में ईंधन और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। पेट्रोल पंपों और एलपीजी वितरकों के पास कोई कमी नहीं है। जनता घबराकर जरूरत से ज्यादा खरीददारी कर रही है, जिससे आपूर्ति व्यवस्था में अनावश्यक बाधा उत्पन्न हो रही है।

केंद्र सरकार के 9 मार्च के आदेश के अनुसार, सभी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां (आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल) उत्पादित गैस की आपूर्ति सबसे पहले घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने होटलों, रेस्तरांओं, अस्पतालों और छात्रावासों जैसे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सिलेंडरों की आपूर्ति में व्यवधान के संबंध में केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है। तेल कंपनियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे व्यावसायिक उपयोग के लिए सिलेंडरों की आपूर्ति में कोई कमी न होने दें और मनमानी कीमतें न वसूलें।

सरकार उन लोगों के खिलाफ युद्ध जैसी कार्रवाई कर रही है जो इस स्थिति का फायदा उठाकर ईंधन का भंडारण कर रहे हैं और उसे काला बाजार में बेच रहे हैं। घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अवैध रूप से उपयोग करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध रूप से सिलेंडर रिफिल करने और कम वजन वाली गैस वितरित करने वाली एजेंसियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। दोषियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और एलपीजी नियंत्रण आदेश 2000 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सिलेंडर की डिलीवरी में देरी, अवैध भंडारण या अधिक कीमत वसूलने की स्थिति में, जनता तुरंत 112 नंबर पर कॉल करके शिकायत कर सकती है। बुकिंग नंबर काम न करने की स्थिति में वैकल्पिक व्हाट्सएप चैनलों के माध्यम से बुकिंग की व्यवस्था की गई है। जनता को निराधार अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। राज्य सरकार तेल कंपनियों के साथ लगातार संपर्क में है और आपूर्ति व्यवस्था को नियंत्रण में रखे हुए है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने कहा कि जिला प्रशासनों को स्थिति स्पष्ट करने के लिए पूर्ण अधिकार दिए गए हैं।

भारत में 'शत्रु सम्पतियों' के प्रबंधन व अधिकरण में जुटा है 'सीईपीआई'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ। शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत लखनऊ में सुल्तान गंज बांध और बनारसी बाग के बीच में एक आलीशान चौरुखा महल स्थित है जिसे आज 'बटलर पैलेस' के नाम से जाना जाता है। इस बटलर पैलेस में गत दिनों कर्नाटक व त्रिपुरा से आए मीडिया प्रतिनिधिमंडल के लखनऊ आगमन पर कस्टोडियन ऑफ इनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया(सीईपीआई) की ओर से एक महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मीडिया प्रतिनिधियों को एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट तथा उससे संबंधित सरकारी कदमों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना था। कार्यक्रम में सीईपीआई के उपसचिव राजेन्द्र कुमार, मुख्य पर्यवेक्षक ब्रिगेडियर यशपाल सिंह, पीआईबी गुवाहाटी के अतिरिक्त महानिदेशक कृपाशंकर यादव, पीआईबी लखनऊ के निदेशक दिलीप कुमार शुक्ला तथा पीआईबी बेंगलूर की सहायक निदेशक करिश्मा पंत मंच पर उपस्थित थे।

भारत में पाकिस्तानी व चीनी नागरिकों की सम्पति होती है 'एनिमी प्रोपर्टी'

कार्यक्रम के दौरान ब्रिगेडियर यशपाल सिंह ने पत्रकारों को सीईपीआई के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, कानूनी दायरे और कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968, उन संपत्तियों पर लागू होता है जो वर्ष 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान चले गए व्यक्तियों या चीन के नागरिकों की थीं और भारत में रह गई थीं। एनिमी प्रोपर्टी भारत के शत्रु घोषित देशों में प्रवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई हैं। यह अधिनियम सरकार को इन संपत्तियों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है, इन्हें शत्रु संपत्ति घोषित करता है और कानूनी वारिसों द्वारा उत्तराधिकार के दावों पर रोक लगाता है, जिससे ऐसी संपत्तियों पर राज्य का नियंत्रण सुनिश्चित होता है। शत्रु संपत्ति अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था और यह पाकिस्तानी नागरिकों के स्वामित्व वाली भारत में स्थित संपत्ति के अधिग्रहण को सक्षम और विनियमित करता है। यशपाल सिंह ने बताया कि आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान चले गए व्यक्तियों की लगभग 9,280 संपत्तियां भारत में मौजूद हैं, जबकि चीनी नागरिकों की 126 संपत्तियां भी इसी श्रेणी में आती हैं। इन संपत्तियों में भूमि, मकान, व्यावसायिक परिसंपत्तियां तथा अन्य प्रकार की संपत्तियां शामिल हैं। ब्रिगेडियर सिंह ने बताया कि एनिमी प्रॉपर्टी के प्रबंधन और निगरानी के लिए सीईपीआई का केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जबकि इसकी शाखाएं मुंबई, कोलकाता और लखनऊ में कार्यरत हैं। प्रारंभ में यह विभाग वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता था, किंतु बाद में इसे गृह मंत्रालय के अधीन स्थानांतरित कर दिया गया।

देशभर में उत्तरप्रदेश में सबसे ज्यादा है 'एनिमी प्रॉपर्टी'

ब्रिगेडियर यशपाल सिंह ने बताया कि लखनऊ शाखा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित एनिमी प्रॉपर्टियों की निगरानी करती है। इन दोनों राज्यों में इस प्रकार की संपत्तियों की संख्या देश में सर्वाधिक है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा उत्तरप्रदेश में लगभग 5,571 तथा उत्तराखंड में 24 एनिमी प्रॉपर्टियां पंजीकृत हैं। इन संपत्तियों की बड़ी संख्या उत्तरप्रदेश के पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में स्थित है। लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, प्रयागराज, अयोध्या, सीतापुर, कौशाम्बी, अमरोहा, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर जैसे जिलों में इनकी उल्लेखनीय उपस्थिति है। ब्रिगेडियर सिंह ने विभाग द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण कार्रवाइयों का भी उल्लेख किया। इनमें नैनीताल में मेट्रोपोल होटल का ध्वस्तीकरण, ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी क्षेत्र में 148 दुकानों से अतिक्रमण हटाना, लखनऊ के हजरतगंज स्थित कबीला रेस्टोरेंट को सील करना तथा विभिन्न जिलों में बहुमूल्य संपत्तियों से अवैध कब्जों को हटाना शामिल है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश से संबंधित एक एनिमी प्रॉपर्टी पर एक माफिया द्वारा अवैध रूप से कई इमारतें खड़ी कर दी गई थीं, किंतु विभाग ने उन्हें ध्वस्त कर भूमि को पुनः अपने नियंत्रण में ले लिया। ब्रिगेडियर यशपाल सिंह के अनुसार विभाग ने कई मूल्यवान संपत्तियों को मॉनिटाइजेशन के माध्यम से सरकार के लिए आय का स्रोत भी बनाया है। उन्होंने कहा कि एनिमी प्रॉपर्टी की पहचान, संरक्षण, प्रबंधन और आर्थिक उपयोग के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसके अंतर्गत सर्वेक्षण, सीमांकन, कानूनी कार्रवाई और मॉनिटाइजेशन जैसे चरण शामिल हैं। कार्यक्रम के समापन पर पत्रकार मंडल को 'बटलर पैलेस' का भ्रमण भी कराया गया तथा जानकारी दी गई।

अधूरा होते हुए भी पूर्णता की कहानी कहता है 'बटलर पैलेस'

लखनऊ में सुल्तानगंज स्थित 'बटलर पैलेस' वर्ष 1907 में सीई डिप्टी कमिश्नर अवध बने सर हारकोर्ट बटलर के नाम पर है। इस पैलेस का नक्शा लखनऊ काउंसिल चैंबर्स की शानदार इमारत के प्रसिद्ध वास्तुकार सरदार हीरासिंह ने बनाया था। राजा महमूदाबाद के इस राज महल की नींव फरवरी वर्ष 1915 में रखी थी यही वजह है कि इसका नाम भी उनसे जुड़ गया। वर्ष 1921 में इस महल का एक सिरा बनकर तैयार हुआ तो गोमती नदी में आई बाढ़ ने उसे तहस-नहस कर दिया जिससे राजा साहब को अपना इरादा बदलना पड़ा और इसका चौथाई हिस्सा ही बन सका। इस शानदार चौतरफा मुख वाले हवेली को चित्ताकर्षक बनावट है जो कि राजस्थानी और भारत-मुगल शैली के मिश्रण से प्रेरित है। बटलर हाउस महमूदबाद के राजाओं के परिवार की संपत्ति था। वर्ष 1965 में भारत-भारत युद्ध के बाद, भारत सरकार ने बटलर पैलेस को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया था। चार कोनों पर चार बुर्ज से सजा ये जाली मेहराबों वाला यह महल राजसी लुक देता है। लखनऊ के परंपरागत शाही दरवाजों का एक शानदार नमूना है। तीन मंजिला इस बटलर पैलेस में कुल 32 कमरे हैं तथा हर कमरा एक विशाल गैलरी नुमा गलियारे में जुड़ता हैं। इस बटलर हाउस में एक अस्तबल, झील भी है। इन दिनों बटलर हाउस की साज सज्जा का कार्य चल रहा है। यह इमारत अधूरी व जर्जर होते हुए भी अपने आप में पूरी एक कहानी है। पहली झलक में बटलर हाउस किसी बड़े राजा के महल से कम नहीं लगता और आसपास का खुलापन इसे और विशालता प्रदान करता है।

'भाषा' की मासिक काव्य गोष्ठी में होली के गीतों की धमाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। स्थानीय 'भाषा' साहित्य मंच द्वारा होली और महिला दिवस पर आधारित ऑनलाइन काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। सरिता श्रीवास्तव ने संचालन किया। विद्या कृष्णा ने गोष्ठी की अध्यक्षता की। विद्या कृष्णा ने भावपूर्ण सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी। संस्थापिका डॉ उषा श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित किया तथा सभी को पर्वों के महत्व के बारे में बताया। इस काव्य गोष्ठी में रचनाकार विजय स्याल, ग़ज़लकार विद्या कृष्ण, डॉ सुमन मल्होत्रा, ऋता शेखर, डॉ उषा श्रीवास्तव, सरिता श्रीवास्तव व राजेश्वरी मालवीय ने होली व महिला दिवस के संदर्भ में अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। पूरी गोष्ठी में होली के गीतों की धूम रही। डॉ उषा श्रीवास्तव ने धन्यवाद दिया।

मोक्षवाहिनी वाहन के रखरखाव के लाभार्थियों का किया सम्मान

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। राजस्थान संघ कर्नाटक ट्रस्ट द्वारा पिछले 26 वर्षों से दानदाताओं के सहयोग से वर्तमान में 1 मोक्षरथ व 4 मोक्षवाहिनी वाहन निःशुल्क अंतिम यात्रा हेतु शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इस सहयोग क्रम में लेडवेल लाइटिंग सॉल्युशन के धर्मीचंद सुरेन्द्रकुमार टोडरवाल परिवार ने 1 वर्ष तक मोक्षवाहिनी वाहन के रखरखाव खर्च का लाभ लिया। ट्रस्ट के चेयरमैन अनिल संकलेचा, अध्यक्ष कैलाश संखलेचा, उपाध्यक्ष अरविंद खींवसरा, कोषाध्यक्ष भोपाल सोनवाड़िया, सदस्य अभियान चेयरमैन प्रकाश भोजाणी ने लाभार्थी परिवार का सम्मान कर धन्यवाद दिया।

हनुमान सेवा समिति की ओर से 'हनुमान जन्मोत्सव' 2 अप्रैल को

गोड़वाड़ भवन में सजाई जाएगी हनुमानजी की विशेष झांकी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर की जानी मानी संस्था 'हनुमान सेवा समिति' अपनी 31वीं वार्षिक प्रस्तुति के रूप में गुरुवार 2 अप्रैल को गोड़वाड़ भवन में 'श्री हनुमान जन्मोत्सव' का आयोजन कर रही है। समिति के मदन माहेश्वरी ने बताया कि गुरुवार को अपराह्न 3 बजे से सभा स्थल पर संगीतमय सुन्दरकांड का पाठ रखा गया है जिसमें जसवंतगढ़ नागरिक परिषद के मुख्य हरिकिशन सारड़ा और उनकी टीम द्वारा संगीतमय सुन्दरकांड की प्रस्तुति दी जाएगी। शाम को 6 बजे से इस वर्ष बेंगलूरु के गायक प्रभात करनाणी व शाम 7 बजे से बनारस की सुप्रसिद्ध गायिका पुष्पा बनर्जी इस आयोजन में हनुमानजी के भजनों की प्रस्तुति देंगे। रात्रि 9.30 बजे मंगल आरती व महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में श्री हनुमान जी की विशेष झांकी सजाई जाएगी।इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए हनुमान सेवा समिति के साथ शहर की अनेक सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, जैसे अग्रवाल समाज कर्नाटक, माहेश्वरी सभा, स्वास्तिक सेवा संघ, श्री श्याम मंदिर ट्रस्ट, श्री गोपीकृष्ण संकीर्तन मंडल, राधिका मंडल, आरएलवी भक्त मंडल, श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज, सौरभ सांस्कृतिक संस्था, श्याम दीवाने, आपणो परिवार , मारवाड़ी युवा मंच, नोखा नागरिक परिषद, जसवंतगढ़ नागरिक परिषद, विप्र फाउण्डेशन जोन 18, गौड़ ब्राह्मण संघ कर्नाटक, खांडल विप्र शाखा सभा, श्याम निःस्वार्थ परिवार, कर्नाटक प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन, श्री श्याम मंडल, श्री दादी धाम प्रचार समिति, मां शाकम्बरी सेवा समिति, श्री श्याम परिवार कीर्तन मंडल, श्री श्याम सखा परिवार, श्री श्याम सेवा संघ, माहेश्वरी महिला संगठन आदि जुड़ी हुई हैं ताकि इन सबके प्रयासों से अधिक से अधिक श्रद्धालु हनुमान जन्मोत्सव में शामिल हो सकें। समिति के वरिष्ठ सदस्य व युवा सदस्य जन्मोत्सव की तैयारियों में जुटे हुए हैं।

मैं आरएसएस से हूं, लेकिन आसन किसी भी विचारधारा या पार्टी से परे है: राधाकृष्णन

नई दिल्ली/भाषा। राज्यसभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन ने बृहस्पतिवार को कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से हैं लेकिन लेकिन सदन का आसन किसी भी विचारधारा या पार्टी से परे है।

वह राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे की एक टिप्पणी का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने सदन में टेलीविज़न के मॉनिटर पर दिखाई जा रही अपनी एक पुरानी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा यह शर्ट अलग है लेकिन वह शर्ट पूरी तरह से आरएसएस की है।

इस पर राधाकृष्णन ने जवाब दिया: वह मेरी पुरानी फ़ोटो है जो दिखाई जा रही है। मैं आरएसएस से हूं, इसमें कोई शक नहीं है और मैं इससे कभी इनकार नहीं करूंगा।'' उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा जहां तक मुझे पता है कि आसन कोई आरएसएस नहीं होता, कोई कांग्रेस नहीं होता है।''

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company, 6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51 and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**,
(*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.
HEAD OFFICE : DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT, New Media Company, 6/4, Cantonment Station Road, Bangalore 560051. Editorial : 080-25363030 / 9945488003. For Advertisement : 9945488002 - email : news@dakshinbharat.com/**RNI No. 58061/93.**